स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–24, अंक–8

श्रावण–भाद्रपद 2073, अगस्त 2016

संपादक

अजेय भारती

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4

समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज **39**

कवर चतुर्थ पेज **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

एफडीआई है खतरनाक

डॉ. अश्वनी महाजन

1 कवर पेज

2 कवर द्वितीय पेज

10 मुद्रा नीति
राजन के साथ ही मौद्रिक एकाधिकार के युग का अंत
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

14 मुद्दा
विनाशक होगा दालों का आयात
.... देविन्दर शर्मा

16 अर्थव्यवस्था
काले धन का दोहरा संकट
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

18 उदारीकरण के 25 वर्ष
उदारीकरण ने डुबोया या पार लगाया!
.... विक्रम उपाध्याय

20 पर्यावरण
प्रकृति की पुकार
.... रेणु पुराणिक

22 संस्मरण
सामाजिक समरसता के प्रणेता – माननीय बाला साहब देवरस
.... डॉ. विजय वशिष्ठ

25 जल
जलाशयों की गाद हटाने में बाढ़ का उपयोग
.... कृष्ण गोपाल 'व्यास'

27 आयुर्वेद
'अमृतं वै आपः'–अमृत देने वाला जल
.... वैद्या हेतल एस. दवे

30 रपट
देश भर में एफडीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तथा ज्ञापन
.... स्वदेशी संवाद

33 व्हाटसएप
ज्ञान भंडार

38 रिपोर्ट
हमारा अधिकांश व्यापार घाटा चीन से वस्तुओं के आयात के कारणः *श्री कश्मीरी लाल*

पाठकनामा

तन–मन को गौरवान्वित करता है 'स्वदेशी' शब्द

आज जबकि आधुनिकता और उससे संबंधित दैनिक जीवन में आने वाली विदेशी कंपनियों की उपयोगी चीजें अपना अस्थायी प्रभाव डालकर कुछ गुमराह करने की नाकाम कोशिश में लगी है, वहीं स्वदेशी शब्द भारतीय दैनिक जीवन के संस्कार में शामिल होकर उन्हें चुनौती और पछाड़ता दिखाई दे रहा है। ताजा उदाहरण बाबा रामदेव का पतंजलि उत्पाद है। किसी चीज की सफलता तभी मानी जाती है, जब देश के बच्चे–बच्चे की जुबान पर वह रट जाए। अब अपने देश का बच्चा कहता है– ''मम्मा मुझे बाबा वाली चॉकलेट चाहिए, बाबा वाला नूडल्स चाहिए..... और भी इत्यादि''।

दूसरी तरफ हमारे युवा और बुजुर्ग अब अपने देश की सोंधी मिट्टी में बने उत्पाद पंसद करने लगे हैं। स्वदेशी दुकानों पर और मेलों में भीड़ उमड़ती दिखाई पड़ रही हैं। अब जब तन–मन में स्वदेशी होगा तो भारतीय होने का गर्व अपने आप मस्तक पर अंकित हो जायेगा। हमारे देश में तमाम आंदोलन चले। लेकिन वे राजनैतिक रहे, व्यवस्था के खिलाफ रहें। परंतु स्वदेशी, जो हमारे तन–मन और सुबह–शाम को संचालित करने वाला शब्द है, आज स्वयं में एक आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। आजादी की लडाई में स्वदेशी आंदोलन जरूर चला था परंतु उसका रूप कुछ अलग और राजनैतिक था। आज का स्वदेशी हमारे देश का संस्कार निर्मित करने वाला आंदोलन है। मिट्टी के कच्चे मकान अब दूर की बात हो गये हैं। परंतु उन्हीं नवर्निमित बिल्डिंगों पर कच्चे मकानों के घपरैल का नक्शा बनाकर नक्काशी की जाती है...... ये क्या हैं? और कुछ नहीं, अपनी परंपरा और भारतीय रीति–रिवाज से मोह और आकर्षित करने वाला एक विचार है, जो हमको स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

स्वदेशी पत्रिका हमारे ऐसे ही स्वदेशी संस्कार को निर्मित करने वाली और सूचना प्रधान पत्रिका है। जो इस विचारधारा को वैचारिक आंदोलन में बदलती दिखाई दे रही है। इसमें उपस्थित सामग्री एवं लेख प्रशंसनीय और सराहनीय है।

डॉ. आलोक दीपक, *पालम, नई दिल्ली*

*****

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

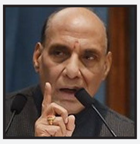

घाटी के हालात के पीछे है पाकिस्तान, पडौसी से अब बात कश्मीर पर नहीं, पीओके पर होगी।

राजनाथ सिंह
गृहमंत्री

मेरा उनके (रघुराम राजन) साथ अनुभव अच्छा रहा है और मैं उनके काम की सराहना करता हूं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बारे में) मैं जो भी कहूंगा, वह समस्या पैदा करने वाला होगा।

रघुराम राजन
रिजर्व बैंक गवर्नर

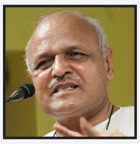

राजन के साथ की मौद्रिक एकाधिकार के युग का होगा अंत।

प्रो. भगवती प्रकाश
प्रख्यात अर्थशास्त्री

संपादकीय

कश्मीर तोड़ने वाले से कहीं ज्यादा जोड़ने वाले

जम्मू कश्मीर नहीं, सिर्फ घाटी का कुछ हिस्सा उबल रहा है। कश्मीर घाटी के कुछ सौ लोग ही पूरे भारत की नाक में दम कर रहे हैं। पाकिस्तान इन्हीं की बदौलत भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहीं के कुछ नेताओं को आजादी के नारे लगाने और पत्थर बरसाने के पैसे मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी का यह क्षेत्र सबसे छोटा है। इस राज्य के तीन प्रमुख संभागों में जम्मू संभाग 12,378 वर्ग किलोमीटर में, लद्दाख संभाग 33,554 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और कश्मीर घाटी संभाग केवल 8,639 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हैं। संख्या के दृष्टिकोण से भी घाटी संभाग जम्मू के बाद दूसरे स्थान पर लगभग 55 लाख की आबादी वाला क्षेत्र है, जहां आंतकवाद का बीज 80 के दशक में बोया गया और उसे अभी तक पनपने दिया गया। घाटी का कुपवाड़ा जिला आंतकवाद का सबसे प्रमुख गढ़ है। यहीं से वर्ष 1988–89 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने अपनी शुरूआत की थी और यहीं से होकर ज्यादातर कश्मीरी आतंकवादी पाकिस्तान प्रशिक्षण के लिए जाते रहे हैं या वहां से प्रशिक्षित होकर भारत में घुसपैठ करते रहे हैं। कुपवाड़ा के बाद बारामुला सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित जिला है। पाकिस्तान की सीमा से लगे होने के कारण यहां से लगातार घुसपैठ होती रही है। इसी जिले में सोपोर है जहां, अक्सर आंतकवाद की घटनाएं सुनाई देती हैं। श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूर बडगाम भी आतंकवादियों का गढ़ है। पाकिस्तान में बैठा हिजबुल मुजाहिद्दीन का मुखिया सैयद सलाउद्दीन इसी जिले का रहने वाला है और यहां 1988–89 से ही आंतकवादी गतिविधियां संचालित कर रहा है। यही हाल पुलवामा का भी है। यहां भी पाकिस्तानी समर्थक आंतकवादी अपनी जड़े जमा चुके हैं और अल जेहाद नाम का संगठन तेजी से फैल रहा है। अनंतनाग वह जिला है जहां से सबसे अधिक आतंकवादी और अलगाववादी संगठित होकर भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। सबसे अधिक हिंसक घटनाएं भी यहीं हो रही हैं।

जम्मू कश्मीर में भले ही एक छोटे हिस्से में ही आतंकवाद की आग लगी हैं, लेकिन इसमें स्वाहा होने वालों की संख्या हजारों में है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार वर्ष 1988 से 2016 तक जम्मू कश्मीर में कुल 43,994 लोगों की जान इस आतंकवाद ने ले ली है। इसमें 14,729 आम नागरिक, 6216 पुलिस व सेना के लोग और 23,049 आंतवादी शामिल हैं। यह कयास लगाना मुश्किल नहीं है कि आखिर इतने छोटे हिस्से में इतनी वारदातें कैसे हो सकती हैं। कारण कई हैं और उनमें सबसे प्रमुख कारण है पाकिस्तान द्वारा लगातार कश्मीरी युवकों को भड़काने की कार्रवाई और भारत के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें खूब सारा पैसा और ऐश करने की छूट प्रदान करना है।

लोगों को यह जानने की आवश्यकता है कि एक तरफ कुछ दर्जन लोग कश्मीर में भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वहीं साढ़े तीन लाख से अधिक जम्मूकश्मीर में वे कर्मचारी हैं जो भारत के संविधान को मानकर उसकी रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का व्रत लेते हैं। लगभग 90 हजार कश्मीरी पुलिस बल में हैं जो दिन रात सीमा के भीतर लोगों की जान माल की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ हजार लोग इस्लाम के कारण पाकिस्तान में कश्मीर का विलय या उसे आजाद करने की मांग कर रहे हैं तो उसी घाटी में सदियों से रह रहे लगभग दस हजार कश्मीरी पंडित घाटी से निकाल दिए जाने के बाद भी उसी मिट्टी और उसी संस्कृति से प्यार और मोहब्बत ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। दोस्तों यह कश्मीर भारत के प्राचीन इतिहास का जिंदा मिसाल ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए देश का मस्तक हैं। कुछ लोगों की जिद या भटकाव के चलते इसे दागदार और अहलदा नहीं मान सकते।

एफडीआई के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का खोखलापन इस बात से उजागर होता है कि इन तर्कों में कोई तारतम्य नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो वो नित नए क्षेत्रों के लिए एफडीआई खोलता जाता है और अन्य क्षेत्रें में एफडीआई की सीमा (कैप) बढ़ाता जाता है। – **डॉ. अश्वनी महाजन**

FDI है खतरनाक

हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा, नागरिक उड्डयन, दवा और सुरक्षा सेवाओं सहित कुल 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों में और ढील देते हुए विदेशियों को 100 प्रतिशत तक निवेश को अनुमति प्रदान की है। यही नहीं सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण और भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों के विपणन में भी स्वचलित रूट से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश खोल दिया है। फार्मा (दवा निर्माण) क्षेत्र में स्वचालित रूट से 74 प्रतिशत और अनुमति द्वारा 100 प्रतिशत ब्राऊन फील्ड निवेश की अनुमति दी गई है। ध्यान रहे ब्राऊन फील्ड निवेश का मतलब है पहले से चल रही कंपनियों को खरीद की अनुमति। इन सब निर्णयों के बाद प्रधानमंत्री इस बात में गौरव महसूस कर रहे हैं कि 'आज भारत में, अधिकतर क्षेत्र स्वचालित रूट से एफडीआई के लिए खुल चुके हैं।'

ध्यान रहे कि रक्षा के क्षेत्र में अभी तक अनुमति द्वारा ही 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति थी और वह भी आधुनिक और अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ आर्ट) प्रौद्योगिकी के लिए ही। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई रियायतों में अत्याधिक (स्टेट ऑफ आर्ट) प्रौद्योगिकी की शर्त को भी हटा लिया गया है। एकल ब्रांड खुदरा के क्षेत्र में एफडीआई में लगाई पूर्व की शर्त कि विदेशी निवेशकों को कम से कम 30 प्रतिशत भारत से ही खरीद करनी होगी, को भी हटा लिया गया है। माना जा रहा है कि शर्त में इस ढील को इसलिए दिया गया है, ताकि एप्पल नाम की मोबाईल कंपनी अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इससे पहले भी नरेन्द्र मोदी

सरकार ने रेलवे, बीमा, पेंशन फंडों समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई को खोलने का काम किया है।

नवंबर 2015 में सरकार ने रक्षा और नागरिक उड्डयन समेत 15 क्षेकों में एफडीआई में ढील दी थी। उल्लेखनीय बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए मल्टी ब्रांड समेत सभी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को लगातार बढ़ाने का काम करती रही, आज मोदी सरकार की एफडीआई संबंधित निर्णयों का विरोध करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता श्री जयराम रमेश का कहना है कि ''यह रघुराम राजन द्वारा रिजर्व बैंक गवर्नर के पद को छोड़ने की घोषणा के बाद सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया यह निर्णय है.... घरेलू निवेश कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और केवल एफडीआई द्वारा हम देश के समक्ष समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेंगे। एफडीआई आर्थिक संवृद्धि का महत्वपूर्ण औजार है, लेकिन यह आर्थिक संवृद्धि के लिए मुख्य औजार नहीं है।''

एफडीआई के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का खोखलापन इस बात से उजागर होता है कि इन तर्कों में कोई तारतम्य नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो वो नित नए क्षेत्रों के लिए एफडीआई खोलता जाता है और अन्य क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा (कैप) बढ़ाता जाता है। लेकिन विपक्ष में रहने पर वही राजनीतिक दल उसी विदेशी निवेश नीति का विरोध करता दिखाई देता है। सत्ताधारी दल एफडीआई द्वारा अतिरिक्त संसाधन और नवीनतम प्रौद्योगिकी आने की बात करता है तो विपक्ष में रहते हुए वही दल कहता है कि देश की समस्याओं के समाधान का एफडीआई रास्ता नहीं है और कहता है कि देश का विकास विदेशी संसाधनों से नहीं हो सकता और घरेलू निवेश विदेशी निवेश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

विदेशी मुद्रा–कितनी आई, कितनी गई

(Million Dollar) (दस लाख डालर)

वर्ष	कुल एफडीआई प्रवाह	रायल्टी, ब्याज, वेतन, डिविडेंड के रूप में बहिर्गमण
2000–01	4029	7686
2001–02	6130	7585
2002–03	5035	6968
2003–04	4322	8409
2004–05	6051	9572
2005–06	8961	12263
2006–07	22826	16639
2007–08	34843	19340
2008–09	41873	21418
2009–10 (P) (+)	37745	21061
2010–11 (P) (+)	34847	27538
2011–12 (P)	46556	26131
2012–13 (P)	36860	31731
2013–14 (P)	24299	34380
2014–15 (P)	30931	36466
कुल (2000–01 से 2014–15)	**345308**	**287187**

स्रोत : 1. Department of Industrial Policy and Promotion, GOI
2. Reserve Bank of India, Handbook of Statistics 2015-16 and various Bulletins.

एफडीआई के पक्ष में सरकारी तर्क

सरकार कहती है कि देश में संसाधनों की कमी है और विकास (खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्रों में) वित्तीयण के लिए हमें अतिरिक्त संसाधन चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ेगा और विदेशों पर निर्भरता भी कम होगी। आज देश में बड़ी मात्रा में आयात हो रहे हैं, जबकि निर्यात कहीं कम है, जिसके चलते हमारा व्यापार घाटा और विदेशी भुगतान घाटा (ठंस. ंदबम व िच्ंलउमदज) अत्यधिक है। उसकी पूर्ति के लिए हमें एफडीआई और एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेश) की जरूरत है। यदि हमें इन माध्यमों से विदेशी मुद्रा नहीं मिलती तो हमारे रूपए का भारी अवमूल्यन होने की आशंका है।

आधारहीन हैं सरकारी तर्क

एफडीआई के पक्ष में सरकारी तर्कों को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह तर्क कि विदेशी निवेश के प्रवाह से रूपए के अवमूल्यन को रोका जा सकता है, समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पिछले 25 वर्षों में रूपया 18 रूपए प्रति डालर से गिरता हुआ, 68 रूपए प्रति डालर तक पहुंच चुका है और यही वह कालखंड है, जब हमें अधिकतम एफडीआई प्राप्त हुई है। पिछले मात्र 15 वर्षों में ही 400 अरब डालर से ज्यादा एफडीआई हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा भारी विदेशी संस्थागत निवेश भी हमें प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह है कि एक तरफ तो एफडीआई से हमें डालर मिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर रायल्टी, ब्याज, डिविडेंट, वेतन समेत कई नाम से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा ये कंपनियां भारत से ले जाती हैं।

विदेशी कंपनियां हालांकि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर ले जाती रही है, वर्ष 2010 से यह प्रक्रिया और तेज हुई हैं, अप्रैल 2010 से पहले भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा अपनी मूल

एफडीआई बनाम एफडीओ – 2011–12

आकलित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या – 28	(करोड़ रू. में)
1. 28 कंपनियो की कुल बिक्री	112,654
2. अंश पूंजी	1,954
3. रायल्टी भुगतान	1,359
4. सूचना प्रौद्योगिकी शुल्क	149
5. डिविडेंट भुगतान	2,706
6. आयात (कुल मूल्य)	18,984
7. प्रोफेशनल और सलाहकार शुल्क	379
8. अन्य भुगतान	2,756
9. सकल प्रत्यक्ष विदेशी बहिर्गमण, यानि सकल एफडीओ (ए)	26,334
10. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से अर्जित कुल विदेशी मुद्रा (बी)	10,696
11. निवल प्रत्यक्ष विदेशी बहिर्गमण यानि नेट एफडीओ (ए–बी)	15,638

स्रोतः *28 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वार्षिक रपटों से आकलित*

कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होने पर भेजी जाने वाली रायल्टी की 20 लाख डालर और घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत और निर्यात बिक्री पर 8 प्रतिशत तक रायल्टी भेजने की सीमा थी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं होने पर घरेलू बिक्री पर 1 प्रतिशत और निर्यात बिक्री पर 2 प्रतिशत रायल्टी भेजने की अनुमति थी। अप्रैल 2010 को दिसंबर 2009 से प्रभावी, आदेश द्वारा विदेशों को रायल्टी भेजने पर तमाम सीमाओं को हटा दिया गया। इसके चलते रायल्टी के माध्यम से विदेशों को रायल्टी भुगतान की होड़ लग गई। प्रेस नोट 8 (2009), डीआईपीपी, वाणिज्य मंत्रालय।

यदि सरकार का यह तर्क कि विदेशी निवेश के द्वारा हम अपने विदेशी मुद्रा भुगतान के अंतर को पाट सकते हैं, तथ्यात्मक रूप से गलत है। निम्न तालिका में हम देखते हैं कि वर्ष 2000–01 से 2014–15 तक 345.3 अरब डालर हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त हुए और इस दौरान विदेशों को 287.2 अरब डालर रायल्टी, ब्याज, डिविडेंट और वेतन इत्यादि के रूप में विदेश भेज दिए गए। इसके अलावा ये कंपनियां, टैक्स की चोरी और विदेशी मुद्रा हस्तांतरण के उद्देश्य से 'ट्रांस्फर प्राईसिंग' जैसे तरीकों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा विदेशों में हस्तांतरित कर देती हैं।

ट्रांस्फर प्राईसिंग

हम जानते हैं कि रायल्टी, डिविडेंट इत्यादि के माध्यम से कानूनी रूप से तो ये कंपनियां भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर ले ही जाती हैं, ट्रांस्फर प्राईसिंग जैसे बदनाम तरीकों से भी विदेशी मुद्रा बाहर भेजी जाती हैं, ट्रांस्फर प्राईसिंग द्वारा करों की चोरी और विदेशी मुद्रा हस्तांतरण के हजारों मामले आयकर विभाग और न्यायालयों में लंबित हैं। ट्रांस्फर प्राईसिंग जैसी तरकीब से आयातों का मूल्य बढ़ा कर और निर्यात का मूल्य घटा कर आंका जाता है।

आपको विदित ही होगा कि विदेशी कंपनियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से ट्रांस्फर प्राईसिंग की कुटिल विधि द्वारा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा विदेशों को प्रेषित हो जाती है। ऐसे हजारों मामले पहले से ही विभागीय और न्यायालय के स्तर पर लंबित है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा विदेशों में चली जाती है, बल्कि कर चोरी का भी ये बड़ा स्रोत है।

एक अन्य कारण जो विदेशी मुद्रा बहिर्गमण का मुख्य मार्ग है, वह है उपकरणों, कच्चे माल और अन्य प्रकार के आयात। विदेशी कंपनियों की आयात प्रवृत्ति घरेलू कंपनियों से कहीं अधिक होती है। श्री शेखर स्वामी, 28 विदेशी कंपनियों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद लिखते हैं कि वर्ष 2011–12 में मात्र इन्हीं 28 कंपनियों (जो विभिन्न उद्योगों में संलग्न थी) के द्वारा 10,696 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा कमाई, जबकि इनके द्वारा 26,334 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा बाहर भेजी गई। इसे श्री शेखर स्वामी एफडीओ (यानि प्रत्यक्ष विदेशी बहिगर्मण) कहते हैं। यानि देश को 15,638 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ। इसलिए केवल यही नहीं देखना होगा कि, विदेशी कंपनियों द्वारा एफडीआई कितना आया, यह भी महत्वपूर्ण है कि एफडीओ कितना गया।

यह तालिका श्री शेखर स्वामी के 11 अप्रैल 2013 में हिन्दु बिजनेस लाईन में प्रकाशित लेख से उद्धृत की गई है

विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रभुत्व

सामान्यतः एफडीआई समर्थकों द्वारा यह कहा जाता है कि जो क्षेत्र पहले विकसित नहीं हैं, उनका विकास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश द्वारा संभव है। वे इस संबंध में आटोमोबाईल, चिरजीवी उपभोक्ता वस्तुओं (इलैक्ट्रानिक्स सहित) आदि के उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि इन वस्तुओं के उत्पादन बढ़ने से न केवल आयातों पर निर्भरता घटती है, बल्कि उपभोक्ता के पास चयन का अधिकार भी आता है। कारों, टीवी, एसी और इलैक्ट्रानिक्स के उदाहरण भी दिए जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसके साथ ही हमारे बाजार विदेशियों के हाथ में जाते जा रहे हैं। कार के क्षेत्र में मात्र 14 प्रतिशत बाजार ही भारतीय कंपनियों के पास है, टीवी का 27 प्रतिशत और एसी का 42 प्रतिशत बाजार भारतीयों के पास है। इसलिए उपभोक्ताओं को चयन के अधिकार के नाम पर अभी तक की सरकारों ने, मध्यम वर्ग का एक बड़ा बाजार लगभग पूरी तरह से विदेशी हाथों में सौंप दिया

है। बढ़ते मध्यम वर्ग का पूरा फायदा आज भारतीय कंपनियां कम और विदेशी ज्यादा उठा रहे हैं।

अपरिपक्व तर्क

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि पदार्थों की मार्केटिंग (विपणन) में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति के संदर्भ में सरकार का तर्क यह है कि इससे कृषि पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकेगा। यह तर्क वास्तव में अपरिपक्व ही कहा जायेगा, क्योंकि इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव अलग ही प्रकार का है। वास्तव में यदि हम सोचें कि विदेशी कंपनियों के आने से खाद्य पदार्थों की बरबादी घटेगी तो हमारी भूल होगी। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ें बताते हैं कि अमरीका, यूरोप और अन्य विकसित देशों में खाद्य पदार्थों की बरबादी भारत और एशियाई देशों से कहीं ज्यादा है। यूरोप में प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों की बरबादी 280 किलोग्राम है, अमरीका में 295 किलोग्राम है, जबकि एशियाई देशों में यह मात्र 125 किलोग्राम है, खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) का कहना है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित खुदरा व्यापार इसका प्रमुख कारण है। एफएओ का कहना है कि स्तरीय उत्पादों की सुनिश्चितता के नाम पर किसानों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों को उसके भार, आकार, दिखावट आदि के नाम पर नकार देते हैं। इसलिए बड़ी मात्रा में कृषि पदार्थ खेत से बाहर ही नहीं आ पाते और वहीं सड़ जाते हैं। इसलिए ऐसे उत्पाद जो मानवीय उपभोग के लिए उपलब्ध हो सकते थे या तो सड़ जाते हैं या पशुओं का आहार बनते हैं। एफएओ का यह भी कहना है कि बड़े स्टोरों द्वारा कृषि पदार्थों को शेल्फ पर सजाया जाता है और वहां इन पदार्थों की बड़ी रेंज सजाई जाती है। विभिन्न प्रकार के और विभिन्न ब्रांडों के सामान वहां रखे जाते हैं ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। उपभोक्ताओं की भी यही इच्छा होती है। लेकिन ये उत्पाद कई बार एक्सपायरी से पहले बिक नहीं पाते। एक्सपायरी नजदीक आने पर उपभोक्ता उन्हें पहले ही नकार देते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को विदेशी कंपनियां बचाने वाली तो कतई नहीं, बल्कि उनकी बरबादी का कारण जरूर बनने वाली हैं।

प्रतिरक्षा में विदेशी निवेश

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के समर्थकों का कहना है कि इससे आधुनिक और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देश में आएगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि पूर्व में विदेशी निवेश के लिए जो शर्त लगाई गईं थी, उनको शिथिल करते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की शर्त को हटा दिया गया है। यह सर्वविदित ही है कि विकसित देशों द्वारा प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मनाही है। अमरीकी सरकार तो इस मामले में सबसे ज्यादा सख्त है।

अमरीकी कानून अपनी कंपनियों द्वारा प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कतई इजाजत नहीं देता, चाहे वे उन देशों में उत्पादन भी कर रही हैं।

अमरीकी कानून अपनी कंपनियों द्वारा प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कतई इजाजत नहीं देता, चाहे वे उन देशों में उत्पादन भी कर रही हैं। इसलिए चाहे हम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दे भी दें तो भी प्रौद्योगिकी आने वाली नहीं है। यह सही है कि आज देश प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर है और लड़ाकू विमान, उपकरण, गोला–बारूद विदेशों से आयात हैं। इससे न केवल बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, बल्कि उनकी ऊंची कीमत भी देश को चुकानी पड़ती है। सोवियत रूस के विघटन के बाद भारत को काफी हद तक अमरीका और पश्चिमी यूरोप पर निर्भर होना पड़ रहा है। कहने को तो विदेशी निवेश को अनुमति देने से इन उपकरणों का देश में उत्पादन होने पर विदेशों पर निर्भरता घटेगी, लेकिन प्रबंधकीय नियंत्रण विदेशियों के हाथ में जाने से देश के सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं। ये कंपनियां युद्ध की स्थिति में अपनी सरकारों के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हो सकती है। इसलिए देश की कंपनियों में ही प्रतिरक्षा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है।

विदेशी निवेश के संदर्भ में मुख्य समस्या नीति निर्धारकों की मानसिकता से संबंधित है, जिनका यह मानना रहता है कि देश की हर समस्या का समाधान विदेशी निवेश से हो सकता है। वास्तव में प्रश्न यह नहीं है कि प्रतिरक्षा में विदेशी निवेश होना चाहिए या नहीं, असली प्रश्न यह है कि क्या इससे देश आत्मनिर्भर होगा या नहीं। स्वतंत्रता के बाद प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हो पाई और अधिकतर उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में ही होता रहा। आवश्यकता इस बात की है कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा मिले। जहां भी सरकार ने शोध और विकास पर ध्यान दिया, देश ने वहां–वहां अभूतपूर्व प्रगति की। अंतरिक्ष क्षेत्र में पीएसएलवी, अग्नि मिसाईल, आणविक हथियार आदि इसके जीते–जागते उदाहरण हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार शोध और विकास कार्यों को बढ़ावा देकर प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता बढ़ाए। दुर्भाग्य से अभी चीन से आ रहे निवेश को भी प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में प्रतिरक्षा विदेशी निवेश में सतर्कता बरतनी होगी। ❑❑

राजन के साथ ही मौद्रिक एकाधिकार के युग का अंत

वर्ष 2008 में डा. मनमोहन सिंह द्वारा अवैतनिक आर्थिक सलाहकार व 2012 में देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाये जाने के पूर्व राजन जी–7 कहे जाने वाले औद्योगिक देशों व विशेषकर अमेरिकी नियंत्रण में कार्यरत एवं विकासशील देशों की नीतियों को औद्योगिक देशों के हित में प्रभावित करने के लिये जाने वाले मुद्राकोष के भी मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर 2003 से 2007 तक रहे हैं। – **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से राजन की विदाई के साथ ही, देश की मौद्रिक नीति भी एक वैयक्तिक एकाधिकार से मुक्त हो सकेगी। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रिजर्व बैंक अधिनियम में जून माह में किये परिवर्तन के बाद अब देश की मौद्रिक नीति का निर्धारण अकेले रिजर्व बैंक गवर्नर के स्थान पर, अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की तरह, छः सदस्यीय 'मौद्रिक नीति समिति' करेगी। एक व्यक्ति की अदूरदर्शिता, यत्किंचित निहित हितों या किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के विरूद्ध जब छः लोगों के संयुक्त विवेक से देश की मौद्रिक नीति तय होगी तो वह देश की आवश्यकताओं, विकास की प्राथमिकताओं व व्यावहारिकता के अधिक निकट होगी। संभवतः अब मौद्रिक नीति की अगली समीक्षा इस नव–प्रस्तावित समिति द्वारा की जायेगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार व रिजर्व बैंक के तैबीसवें एवं सर्वाधिक विवादास्पद गवर्नर, रघुराम गोविन्द राजन जिन्हें अब कई लोग इस शीर्ष मौद्रिक पद पर लगभग अवांछनीय ही ठहरा रहे हैं, स्वयं भी अब इस देश में अपनी कोई भूमिका देखने के बजाय, पुनः अमेरिका प्रस्थान करने वाले हैं। वर्ष 2008 में डा. मनमोहन सिंह द्वारा अवैतनिक आर्थिक सलाहकार व 2012 में देश का मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाये जाने के पूर्व राजन जी–7 कहे जाने वाले औद्योगिक देशों व विशेषकर अमेरिकी नियंत्रण में कार्यरत एवं विकासशील देशों की नीतियों को औद्योगिक देशों के हित में प्रभावित करने के लिये जाने वाले मुद्राकोष के भी मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर 2003 से 2007 तक रहे हैं। वर्ष 2012 में 10 अगस्त से मनमोहन सिंह सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में रहने के बाद अब वे विगत तीन वर्षों से रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। उनके विगत 3 वर्ष के कार्यकाल में देश की मुद्रा स्फीति दर एकल अंक की सीमा में ही रही है। तथापि, इस

अपेक्षाकृत न्यून मुद्रा स्फीति दर को भी अति उच्च ठहराते हुये पूरे कार्यकाल में ऊंची ब्याज दरों व अपर्याप्त तरलता से देश में जो आर्थिक गतिरोध उत्पन्न किया है, उसकी पूर्ति निकट भविष्य में असम्भव है। ऊँची ब्याज दरों व अपर्याप्त तरलता के कारण देश में निवेश, नवीन परियोजनाओं की स्थापना, औद्योगिक उत्पादन, उद्योगों की लाभदायकता व निर्यातों में भारी गतिह्रास हुआ है। इस सबसे देश के उद्योग जगत में निराशा, बैंकों के ऋणों की वसूली में गिरावट और अनिष्पादनीय आस्तियों (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) में वृद्धि का दौर आज अत्यन्त चिन्ताजनक स्तर पर है। वस्तुतः विगत 12 वर्षों में उच्च ब्याज दरों से देश ने अरबों रूपये की उत्पादन व निर्यात वृद्धि के जिन अवसरों को खोया है, इसी के कारण देश में निवेश में गतिरोध और करोड़ों युवाओं की रोजगार पाने की आशाओं पर तुषारापात हुआ है। ऊँची ऋण लागतों से देश जिस औद्योगिक रूग्णतावश अपने समकक्ष राष्ट्रों यथा चीन, कोरिया, ताइवान, मलेशिया आदि से पिछड़ा है उसकी भी पूर्त्ति कठिन है।

ब्याज दरें ऊँची होने से ऋण महंगा हो जाता है, निवेश घटता है, रोजगार सृजन अवरूद्ध होता है, ऊँची ऋण लागतों के कारण देश के उद्यम निर्यात बाजार खो देते है, चालू खाता घाटा बढ़ता है। रुपये के मूल्य में गिरावट आती है। कर्ज की लागत ऊँची होने से अनार्थिक हो रहे देश के उद्यम बिकते चले जाते हैं जिन्हें विदेशी कंपनियाँ खरीदती जाती है। ब्याज दरें ऊँची रखने से विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी ऋण प्रतिभूतियों पर ऊँचा लाभ बटोरने

विगत 12 वर्षों में उच्च ब्याज दरों से देश ने अरबों रूपये की उत्पादन व निर्यात वृद्धि के जिन अवसरों को खोया है, इसी के कारण देश में निवेश में गतिरोध और करोड़ों युवाओं की रोजगार पाने की आशाओं पर तुषारापात हुआ है।

में मदद मिलती है। पिछली 12 वर्षों में यही हुआ है और वह भी एक व्यक्ति जो भी रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, मौद्रिक नीति पर उसके एकाधिकार के कारण देश ब्याज दरें ऊँची बनी रही। अभी जून में मुद्रा स्फीति मात्र 5.77 प्रतिशत थी, वह भी खाद्य पदार्थों व खाद्य पदार्थों में भी दलहनों के उच्च मूल्यों के कारण देश में दलहन उत्पादन 1.6 करोड़ टन है व उपभोग 2.3 करोड़ टन होने से यह महंगाई आपूर्ति संकट जनित है और मुद्रा प्रसार जन्य नहीं है। तब भी अगस्त 9 की मौद्रिक समीक्षा में 'राजन' ने रेपो रेट को ऊँचा। 6.5 प्रतिशत के अति उच्च स्तर पर बनाये रखा। रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है और उसी के आधार पर अर्थ व्यवस्था में बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें तय होती हैं। आज डेनमार्क, जापान, स्विट्जरलैंड, आदि कई देशों में तो ब्याज दरें शून्य से नीचे ऋणात्मक है। अमेरिका में 1.25 प्रतिशत हैं। ऐस में भारत में 6.5 प्रतिशत रेपो रेट व 10–14 प्रतिशत की ऊंची बैंक ब्याज दरों से उद्योग बेतहाशा रूग्ण हो रहे हैं। सस्ते आयातों के आगे उद्यम बंदी भी हो रही है। हमारे निर्यातक स्पर्द्धा में बुरी तरह पिछड़ रहे हैं और राजन अपनी ऊँची ब्याज दरों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर अड़े रहे हैं।

आज पूरा विश्व जब निवेशकों के लिये खुला पड़ा है ऐसे में हमारे द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत यह हमारे लिये आर्थिक आत्मघात से कम नहीं है। हमारी सख्त मौद्रिक नीति कहाँ टिक पा रही है? वर्ष 2008 के मेल्ट डाउन के बाद अमेरिका द्वारा 20 खरब डालर (2 ट्रिलियन डालर अर्थात् 1320 खरब रुपये तुल्य) मौद्रिक विस्तार किया गया है व इसी प्रकार जापान व यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा भी क्वाण्टिटेटिव इजींग द्वारा भारी मात्रा में मुद्रा प्रसार करने के कारण देश में 2009–15 के बीच 162 अरब डालर (10 लाख 692 करोड़ रुपयों के तुल्य) विदेश संस्थागत निवेश आ गया। इसके कारण वायदा बाजारों में वस्तु मूल्यों (कमोडिटी कीमतों) में जो उछाल आया, वही देश में मुद्रा स्फीति का एक प्रमुख कारण रहा है। उसके पहले 2001–07 के बीच विदेशी

संस्थागत निवेश मात्र 60 अरब डालर (मात्र 35 प्रतिशत) ही रहा है। वस्तुतः आज की मुक्त अर्थव्यवस्था के युग में अन्य किन्हीं भी प्रमुख देशों की ब्याज दरों में नाम मात्र के परिवर्तन से ही विकासशील देशों में निवेश में भारी उतार चढ़ाव आ जाते हैं। उदाहरणतः वर्ष 2015 में अमेरिकी केंद्रीय बैंक (फेडरल रिजर्व) द्वारा ब्याज दर वृद्धि की संभावनाओं के चलते जहाँ उस वर्ष के अंत में मात्र 25 बेसिस पाइण्ट की वृद्धि पर ही विकासशील देशों से 735 अरब डालर (48 लाख 51 हजार रुपये तुल्य) का विदेशी संस्थागत निवेश बाहर चला गया। इसलिये भारत से भी 2015–16 में 3 अरब डालर के संस्थागत निवेश का शुद्ध बहिर्गमन हुआ। इस निवेश के बहिर्गमन से रुपये की विनिमय दर पर दबाव आना स्वाभाविक था। पहले ही ऊँचे व्यापार घाटे से जो, 22 अरब डालर का चालू खाता घाटा था, उसकी पूर्ति 2015 में आये 44 अरब डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ही हो पायी था। इससे रुपये की कीमत सुरक्षित बनी रही। लेकिन, इसके लिये नवंबर 10, 2015 में 15 क्षेत्रों व जून 20, 2016 को छः माह में ही 9 और क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश खोलने की मजबूरी बन गयी। इसलिये केवल ब्याज दरों को ऊँचा रखने से महंगाई पर काबू करने के लाभ की तुलना में नुकसान अधिक हैं।

वस्तुतः मौद्रिक नीति निर्धारकों को यह विदित होना भी आवश्यक है कि हमारे देश में महंगाई का प्रमुख कारण हमारी आंतरिक मौद्रिक तरलता मात्र ही नहीं होकर, इसके कई कारक है, जिनमें निम्न 3 प्रमुख है–

1. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपने संस्थागत निवेश से वस्तु वायदा बाजारों में लाया जाने वाला उछाल।

2. विदेश व्यापार घाटे व विदेशी निवेश की आय में घाटे से रुपये की विनिमय दर में गिरावट। वर्ष 2011 में रुपये की कीमत 50 रुपये प्रति डालर थी जो गिरकर 66 रुपये से भी नीचे चले जाने से सभी आयातों के दाम रुपयों में 15 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण भी देश में मूल्यों में मूल्य वृद्धि हो रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 27 प्रतिशत तक के आयातों से आज जो महंगाई है वही उसका एक प्रमुख कारण है, रिजर्व बैंक द्वारा इसकी अनदेखी कर केवल ऊँची ब्याज दरों से महंगाई नियंत्रण करने की जिद के कारण देश के उद्यम निर्यात में पिछड़ रहे हैं और घरेलू बाजारों में भी आयात सस्ते होने से ही व्यापार घाटे की उच्चता व रुपये में गिरावट आ रही है।

कृषि प्रसंस्करण सहित सभी प्रकार के नये उद्यमों की स्थापना भी तब ही होगी जब ब्याज दरें व ऋण लागतें कम होती हैं। नये उद्यमों की स्थापना व चलते उद्योगों का विस्तार भी तब ही होता है। विद्यमान उद्यमों के विस्तार व नये उद्यमों की स्थापना से ही देश में रोजगार बढ़ सकता है।

3. देश में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि के अभाव में कृषि उत्पादों सहित अनेक उत्पादों की अपर्याप्त आपूर्ति से भी मूल्य बढ़ते हैं, जैसा दलहन, तिलहन आदि में हो रहा है।

वस्तुतः दूसरी ओर ब्याज दरें कम होने पर तो किसान भी अधिक ऋण लेकर कृषि आदायों व यंत्रों में निवेश करने की सोचता है और उत्पादकता बढ़ाने में सफल होता है। कृषि प्रसंस्करण सहित सभी प्रकार के नये उद्यमों की स्थापना भी तब ही होगी जब ब्याज दरें व ऋण लागतें कम होती हैं। नये उद्यमों की स्थापना व चलते उद्योगों का विस्तार भी तब ही होता है। विद्यमान उद्यमों के विस्तार व नये उद्यमों की स्थापना से ही देश में रोजगार बढ़ सकता है। रोजगार से ही लोगों की आय बढ़ती है, उससे बाजार में मांग व उत्पादन वृद्धि से रोजगार, आय व पुनः निवेश संवर्द्धन से स्वतः स्फूर्त आर्थिक वृद्धि व विकास का चक्र प्रवाहमान होता है। इसी प्रकार ब्याज दरें न्यून होने पर ऋण की लागतें कम होने पर उद्योगों की भी लाभदायकता बढ़ती है, जिससे पुनः रोजगार, आय, उत्पादन व निवेश चक्र प्रवाहमान होता है। दूसरी ओर ब्याज दर कम होने पर सामान्य नागरिकों की भी भवन ऋण, वाहन ऋण आदि की मासिक

किश्त की राशि कम होने से बचने वाली राशि को भी वे बाजार में जब व्यय करेंगे तो उससे भी बिक्री, मांग, उत्पादन वृद्धि व निवेश का चक्र गतिमान होता है। न्यून ब्याज से दरों आकृष्ट होकर ही बड़ी संख्या में लोग गृह ऋण लेकर अपना मकान बनाने से लेकर अनेक प्रकार के संसाधनों की खरीद करते हैं। विगत 12 वर्षों में ऊंची ब्याज दरों व मोदी सरकार बनने के इन 27 महिनों में जो राजन के इस 36 माह के कार्यकाल में ही निकले है, में महंगाई नियंत्रित रही होने पर भी राजन द्वारा जो ब्याज दरें ऊंची रखीं गयी उनसे उपजे आर्थिक गतिरोध की क्षतिपूर्ति अल्पकाल छोड़ मध्यमाविधि में भी संभव नहीं है। इंगलैण्ड में जब 1980 में व 1990 में क्रमशः ब्याज दरें 17 व 15 प्रतिशत रखी गयीं तब वहां भी मंदी फैली व अमेरिका में भी जब 1981–82 में ब्याज दरें ऊंची थी तो वह भी भारी मंदी का शिकार हुआ था। इंग्लैण्ड में वैश्विक मेल्ट डाउन व यूरोपीय ब्रॉण्ड संकट के दौर में जब उनकी विकास दर 2008 में शून्य व 2009 में रसातल में (–) 7 प्रतिशत पर चली गयी तो उन्होंने आधार ब्याज दर, शून्य प्रतिशत तक ले जा कर ही 2010 में आर्थिक वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत व 2011 में 0.75 प्रतिशत कर लेने में सफलता पायी थी। जबकि इस अवधि में वहां महंगाई दर 1.7 से 4.7 प्रतिशत तक भी रही है।

भारत में पिछले 2 वर्षों में मुद्रास्फीति दर लगभग नियंत्रण में ही रही है।

भारत में पिछले 2 वर्षों में मुद्रास्फीति दर लगभग नियंत्रण में ही रही है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर 10 प्रतिशत से न्यून महंगाई दर पर ब्याज दरें ऊँची कर आर्थिक वृद्धि, विकास, निवेश व उद्यमों की लाभदायकता का हनन करने का कोई औचित्य नहीं कहा जा सकता है। दक्षिण कोरिया में तो पिछले 30 वर्षों में महंगाई दर 10 प्रतिशत से ऊँची होने पर भी उन्होंने ब्याज दरें नीची ही रख कर चीन से भी अधिक ठोस प्रगति की है। वहाँ 1980 के दशक दशक में महंगाई 28 प्रतिशत तक भी गयी है। आज दक्षिण कोरिया जिसकी जनसंख्या व क्षेत्रफल 5 प्रतिशत मात्र है, वह विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। विश्व के एक चौथाई जहाजों का निर्माण वहां होता है। भारत के पास लौह खनिज की प्रचुरता से आज भारत के विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश होने के बाद भी विश्व में शिप–बिल्डिंग में हमारा योगदान 0.1 प्रतिशत से भी कम है। यह है हमारी ऊँची ब्याज दरों की विकासरोधी कटार। इसलिये 25 वर्षों के सबसे सशक्त जनादेश से बनी वर्तमान एन.डी.ए. सरकार को ब्याज दरें नीची लाकर अब ही सही देश को द्रुत विकास के पथ पर ले जाना होगा। इस हेतु सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के गठन का जो निर्णय लिया है, वह सही दिशा में लिया कदम है।

ब्याज दरें कम होने पर देश के कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित हो सकते हैं जो उनकी जमा बचतों के ब्याज पर निर्भर हैं। इसके लिये सरकार विशेष जमा योजना, सामाजिक सुरक्षा ब्याज अनुदान या पेंशन कोषों की विशेष योजना के प्रवर्तन से उनकी बचतों पर आय सुरक्षा दे सकती है। लेकिन, आज आधी से अधिक युवा जन संख्या वाले इस देश को ऊंची ब्याज दरों में जकड़ कर रोजगार सृजन विहीन व शाश्वत व्यापार घाटे व मुद्रा अवमूल्यन के दुश्चक्र में फंसाने वाली मौद्रिक नीति के लिए पीढ़ियां राजन जैसे गवर्नरों को कदाचित ही माफ करेंगी। मोदी सरकार ने जून 2016 में रिजर्व बैंक के गवर्नर के मौद्रिक नीति निरूपण के इस एकाधिकारी अधिकार को गवर्नर सहित छः सदस्यीय "मौद्रिक नीति समिति" को सौंपने का जो निर्णय लिया है वह अत्यंत समीचीन है। आशा है अगली मौद्रिक नीति की समीक्षा यह छः सदस्यीय समिति ही करेगी और देश को एक विकासोन्मुख मौदिक नीति के मार्ग पर ले जायेगी।❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

विनाशक होगा दालों का आयात

कुछ भयावह रूप से गलत हो रहा है। जब भारत में किसान उत्तरोत्तर खुदकुशी के लिए मजबूर किए जा रहे हैं, ऐसे समय में मोजांबिक से दालें आयात करने के लिए सरकारों के बीच अनुबंध त्रुटिपूर्ण अर्थनीति का सबूत है, जो अंततः भारतीय किसानों को जड़ से उखाड़ डालेगी। मैं नहीं जानता कि यह जान–बूझकर किया जा रहा है या इसके गंभीर परिणामों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंधकार में रखा जा रहा है।

मुझे याद है कुछ दशकों पहले जब बलराम जाखड़ कृषि मंत्री थे तो उन्होंने भी कुछ अफ्रीकी देशों में दलहनों की खेती कराने और फिर उन्हें आयात करने का प्रस्ताव रखा था। यूपीए सरकार में तब के कृषि मंत्री शरद पवार भी चाहते थे कि भारत म्यांमार और उरुग्वे में दलहन की खेती कराए और बाद में दालों का आयात किया जा सकता है। किंतु इन सारे वर्षों में कृषि मंत्रालय के किसी अज्ञानी नौकरशाह का यह काल्पनिक विचार केवल मीडिया में बयानबाजी तक सीमित रहा। किंतु मुझे बताया गया है कि इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय के नौकरशाह अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं। खबरों के मुताबिक भारत स्थानीय एजेंटों के माध्यम से मोजांबिक में किसानों के नेटवर्क का पता लगाएगा और उन्हें बीज व उपकरणों सहित उचित टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगा। खेती शुरू करने के पहले इन किसानों को आश्वस्त किया जाएगा कि उनकी उपज को भारत सरकार खरीदेगी और खरीदी मूल्य भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होगा।

यदि भारत नियमित रूप से दालों के उत्पादन के लिए मोजांबिक में किसानों का नेटवर्क तैयार कर सकता है तो मैं चकित हूं कि किसानों का ऐसा ही नेटवर्क भारत में क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता। सरकार ऊंची कीमत देने और निश्चित खरीदी का ऐसा ही आश्वासन क्यों नहीं देती, जिससे आसानी से घरेलू उत्पादन बढ़ सकता था और दालों की उपलब्धता बढ़ जाती।

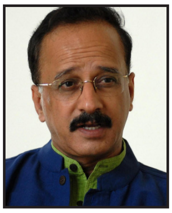

किसी देश के लिए इससे बढ़कर विनाशक कोई बात नहीं हो सकती कि खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य आत्म–निर्भरता की पूर्व शर्त को त्याग दिया जाए। खाद्य आत्म–निर्भरता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय संप्रुभता की कसौटी मानी गई है।

– देविंदर शर्मा

दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कुंजी निश्चित खरीदी में है। सरकार ने चाहे कुछ महत्वपूर्ण खरीफ दलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है जैसे अरहर के लिए प्रति क्विंटल 425 रुपए का बोनस देकर मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, लेकिन दीर्घावधि में सिर्फ कीमत के बल पर उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक सरकार गेहूं–चावल की तर्ज पर दालहन की खरीद नहीं करती, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। यदि सरकार मोजांबिक के किसानों को आश्वासन दे सकती है कि वे जो भी पैदा करेंगे, उसे वह खरीदेगी तो यही आश्वासन देश के भीतर नहीं देने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। भारत को उम्मीद है कि वह मोजांबिक से 1 लाख टन दालें आयात कर सकेगा, जो कुछ ही वर्षों में बढ़कर 2 लाख टन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा तंजानिया, केन्या और मलावी सहित कुछ अन्य अफ्रीकी देशों में भी दालहनों की खेती कराने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। दालों की लगातार बढ़ती घरेलू मांग की पूर्ति के लिए अफ्रीकी उत्पादन पर बढ़ती निर्भरता भारतीय कृषि के मोर्चे पर विनाश का सिलसिला छोड़ जाएगी, जिसके बारे में शायद ठीक से सोचा नहीं गया है। मैं मानता हूं कि खाद्य सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिक जवाबदारी है, लेकिन सिंगापुर जैसे देशों की तरह भारत में यह सुरक्षा आयात से सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए। जब भारत के पास 60 करोड़ किसानों की विशाल फौज हो जो पिछले कुछ दशकों से खेती में संकट का सामना कर रही है तो ऐसी दशा में भारत को चाहिए कि वह व्यापक जनसमूह से उत्पादन करवाएं न कि व्यापक जन–समूह के लिए उत्पादन करवाएं (प्रोडक्शन बाय मासेस, नॉट फॉर मासेस)। 1966 में जब हरित

यदि सरकार मोजांबिक के किसानों को आश्वासन दे सकती है कि वे जो भी पैदा करेंगे, उसे वह खरीदेगी तो यही आश्वासन देश के भीतर नहीं देने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता।

क्रांति शुरू की गई तो यही तो किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बुद्धिमत्ता की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने परिश्रमपूर्वक सरकारी खरीद का तंत्र खड़ा करके देश को भूखमरी के लंबे दुष्चक्र से बाहर निकाला।

किसी देश के लिए इससे बढ़कर विनाशक कोई बात नहीं हो सकती कि खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य आत्म–निर्भरता की पूर्व शर्त को त्याग दिया जाए। खाद्य आत्म–निर्भरता सुनिश्चित करना राष्ट्रीय संप्रभुता की कसौटी मानी गई है। हम न भूलें कि 2007–08 में भारत अनाज के लिए होने वाले दंगों से बच गया जब दुनिया अपूर्व खाद्य संकट का सामना कर रही थी। उस समय कम से कम 37 देशों में ऐसे दंगे हुए थे और वे सारे देश खाद्य के लिए आयात पर निर्भर देश थे। हमारे पास तब प्रचुर खाद्य भंडार था। यह भंडार बनाए रखने की सतत नीति का परिणाम था। दूसरी बात यह है कि हमने खाद्य तेलों के साथ जो गड़बड़ की उससे सबक लेने चाहिए।

इस वक्त देश अपनी जरूरत का 74 फीसदी खाद्य तेल आयात करता है, जिसकी लागत है 70,000 करोड़ रुपए, जबकि हमारे पास देश में ही इसके उत्पादन की क्षमता है। यह सही है कि 2015 में खत्म हुए दशक में खाद्य तेल की खपत दोगुनी हो गई, लेकिन 1993–94 में भारत खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्म निर्भर था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 1985–86 में शुरू किए गए ऑयल सीड्स टेक्नोलॉजी मिशन की बदौलत भारत अगले दस वर्षों में जरूरत का 97 फीसदी खाद्य तेल पैदा कर रहा था। गलत व्यापार नीति के कारण आयात शुल्क बहुत गिरा दिए गए और देश में खाद्य तेल आयात से बाढ़ आ गई। यदि ऊंचे आयात शुल्क से खाद्य तेल आयात पर रोक जारी रहती तो आयात पर जो 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वे किसान के फायदे में खर्च होते। चूंकि तिलहन मुख्यतः वर्षा पर निर्भर मध्यभारत की फसल है, तो कल्पना कीजिए कि इससे किसानों को कितना आर्थिक लाभ होता।

अब दलहनों की बारी है, जिस पर आयात शुल्क शून्य है। अब जब भारत यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है तो यह आशंका बढ़ रही है कि दूध व दूध के उत्पाद, फल–सब्जियां, पोल्ट्री और यहां तक कि गेहूं भी निशाने पर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य आयात पर निर्भरता के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक परिणामों को सोचकर मैं कांप जाता हूं। ऐसी नीति जहां एक ओर किसान को कृषि से बाहर कर देगी वहीं, दूसरी ओर वह देश को 'जहाज से मुंह' तक वाले वजूद के पुराने दिनों में धकेल देगी, जब जहाज से आने वाला अनाज सीधे भूखे लोगों तक पहुंचाया जाता था। ❑❑

काले धन का दोहरा संकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को चेतावनी दी है कि काले धन की घोषणा करके उस पर टैक्स अदा कर दें अन्यथा 30 सितंबर 2016 के बाद सख्त कदम उठाए जाऐंगे। काला धन रखने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। हाल में ही बेनामी प्रापर्टी को जब्त करने का नया कानून संसद ने पारित किया है। मोदी सरकार की शीर्ष स्तर पर ईमानदारी एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए इस कदमों को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रश्न है कि इन सही कदम का अंतिम परिणाम क्या होगा। क्या काले धन पर नियंत्रण से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

आर्थिक विकास का रास्ता निवेश होता है। जैसे एक आटो रिक्शा चालक अपनी 500 रुपए प्रतिदिन की कमाई में 200 रुपए की बचत करे तो दो साल में 1,20,000 रुपए जमा कर सकता है। इस रकम पर बैंक से लोन लेकर वह मोटर कार खरीद कर टैक्सी चला सकता है। तब उसकी आय 500 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 1,000 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। फार्मूला सीधा सा है – आय के अधिकाधिक अंश का निवेश करने से विकास होता है। आय की रकम की खपत करने से विकास शिथिल हो जाता है। यही बात देश की अर्थव्यवस्था पर लागू होती है।

उद्यमी तथा मंत्री द्वारा काले धन का निवेश न करने से जो मंदी आई है वह सरकार द्वारा सफेद धन का निवेश करने से कट जाएगी। जैसे मंत्री ने बिल्डर के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाई। बिल्डर का धंधा पस्त हुआ। लेकिन सरकार ने हाईवे एवं बंदरगाह बनाए। बिल्डर के पस्त होने से आई मंदी, सरकारी निवेश में वद्धि से कट गई। अर्थव्यवस्था साफ भी हो गई और गतिमान भी। यह उत्तम स्थिति है जहां हमें पहुंचना है। – **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

यूपीए सरकार के कार्यकाल में काले धन का बोलबाला था। मंत्री एवं अधिकारी घूस लेकर उद्यमी को राहत देते थे। जैसे मान लीजिए किसी उद्योग के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्लांट लगाना अनिवार्य है। मंत्री जी ने घूस लेकर उस पर कार्यवाही नहीं होने दी। इससे उद्यमी की लागत कम हुई। उसे प्रदूषण नियंत्रण प्लांट में निवेश नही करना पड़ा। प्लांट को चलाने में बिजली खर्च नहीं करनी पड़ी। माल के उत्पादन में उसकी लागत कम आई। उसने प्राफिट कमाया। प्राफिट की रकम का उसने निवेश किया। काले धंधे से निवेश बढ़ा।

दूसरी तरफ मंत्री एवं अधिकारियो ने घूस की रकम का निवेश किया। उन्होंने किसी बिल्डर से पार्टनरशिप स्थापित की और उसके प्रोजेक्ट में निवेश किया। इस प्रकार यूपीए सरकार के कार्यकाल में काले धंधे से निवेश में वृद्धि हुई थी। यही कारण है कि चौतरफा भ्रष्टाचार के बावजूद आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत के सम्मानजनक स्तर पर बनी रही।

मोदी सरकार ने केंद्र के स्तर पर मंत्रियों एवं अधिकारियों का यह गोरखधंधा बंद कर दिया है। फलस्वरूप उद्यमी को प्रदूषण नियंत्रण प्लांट लगाना पड़ रहा है। माल के उत्पादन में उसकी लागत ज्यादा आ रही है। उसके प्राफिट दबाव में है। वह नया निवेश नहीं कर रहा है। मंत्री एवं अधिकारियों की काले धन की आय भी न्यून हो गई है। इनके द्वारा बिल्डर के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाई जा रही है। रीयल एस्टेट में निवेश नहीं हो रहा है। यहां भी मंदी व्याप्त है।

सरकार द्वारा राजस्व का उपयोग निवेश के स्थान पर सरकारी कर्मियों को बढ़े वेतन देने में किया जा सकता है।

लेकिन काले धन पर नियंत्रण से आई यह मंदी आधी कहानी ही बताती है। उद्यमी तथा मंत्री द्वारा निवेश कम हो रहा है यह सच है। परंतु सरकार का राजस्व बढ़ रहा है। टैक्स की चोरी घटी है। प्रधानमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2016 की चेतावनी दिया जाना तथा बेनामी प्रापर्टी को जब्त करने का कानून बनाना इसी दिशा में एक और कदम है। सरकार के राजस्व में आने वाले समय में और वृद्धि होगी। प्रश्न है कि इस राजस्व का उपयोग किस दिशा में किया जाता है। सरकार द्वारा इस रकम का निवेश किया गया तो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा और वह सफेद धन के बल पर चल निकलेगी। उद्यमी तथा मंत्री द्वारा काले धन का निवेश न करने से जो मंदी आई है वह सरकार द्वारा सफेद धन का निवेश करने से कट जाएगी। जैसे मंत्री जी ने बिल्डर के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाई। बिल्डर का धंधा पस्त हुआ। लेकिन सरकार ने हाईवे एवं बंदरगाह बनाए। बिल्डर के पस्त होने से आई मंदी, सरकारी निवेश में वृद्धि से कट गई। अर्थव्यवस्था साफ भी हो गई और गतिमान भी। यह उत्तम स्थिति है जहां हमें पहुंचना है।

दूसरी परिस्थिति में सरकार द्वारा राजस्व का उपयोग निवेश के स्थान पर सरकारी कर्मियों को बढ़े वेतन देने में किया जा सकता है। जैसे वन रैंक वन पेंशन तथा सातवें वेतन आयोग के नाम पर इन्हें बढ़ाकर वेतन दिए जा रहे हैं। सरकारी कर्मियों द्वारा इस रकम से खपत बढ़ाई जा रही है जैसे इनके द्वारा लक्जरी कार खरीदी जा रही है अथवा विदेश यात्रा को जाया जा रहा है अथवा सोना खरीद कर बैंक के लॉकर में रखा जा रहा है। ऐसा करने से सरकार के राजस्व का उपयोग निवेश में नही बल्कि खपत को बढ़ाने में हो जाता है। इसका परिणाम होता है कि निजी क्षेत्र द्वारा काले धन, एवं सरकारी क्षेत्र द्वारा सफेद धन दोनों द्वारा ही निवेश में कटौती हो जाती है।

काले धन पर नियंत्रण का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि राजस्व की वृद्धि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि राजस्व का उपयोग निवेश बढ़ाने के लिए किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में चार चांद लग जाएंगे। इसके विपरीत यदि राजस्व का उपयोग खपत बढ़ाने में किया जाता है तो अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लग जाएगा।

इस दिशा में मोदी सरकार का अब तक का रिकार्ड निराशाजनक रहा है। ईमानदारी से सरकारी राजस्व से खपत को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी निवेश में निरंतर कटौती की जा रही है। इस कटौती का पूरा दुष्प्रभाव दिख नहीं रहा है चूंकि ईमानदारी के निजी निवेश में कुछ वृद्धि भी हुई है। जैसे हाईवे बनाने का ठेका पारदर्शी और बिना घूस लिए दिए जाने से निजी उद्यमी द्वारा हाईवे बनाने में अधिक निवेश किया जा रहा है। परंतु यह उपलब्धि तो यूं भी अपेक्षित थी। इस ईमानदारी से आर्थिक विकास की गति में तेजी आनी थी। लेकिन इस ईमानदारी से केवल सरकार की खपत के दुष्प्रभाव को काटा जा रहा है। जैसे घर का मुखिया दारू पिए और बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसा दे तो परिवार चल निकलता है। वहीं मुखिया ईमानदारी से सोना खरीद कर तिजोरी में रखे और बच्चे की पढ़ाई के लिए निवेश न करे तो परिवार दब जाता है। ऐसा ही मोदी सरकार की कृपा से भारतीय अर्थव्यवस्था का हो रहा है। राजस्व के दुरूपयोग के कारण काले धन पर नियंत्रण अभिशाप बनता जा रहा है। ❑❑

उदारीकरण ने डुबोया या पार लगाया!

देश में जब उदारीकरण की बयार चली, तो वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर चुकी थी। तब हमारे पास बमुश्किल तीन सप्ताह के आयात बिल के लिए उपयुक्त विदेशी मुद्रा का भंडार था, केवल १.२ अरब डॉलर का।

– विक्रम उपाध्याय

लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर उदारीकरण का फायदा आम आदमी को क्या मिला। देश आगे कितना बढ़ा और किसको कितना फायदा पहुंचा? पहले बात प्रतिव्यक्ति आय की करते हैं– इस मामले में भारत को उदारीकरण का बहुत फायदा नहीं हुआ है। हम इतने वर्षों में किसी भी बड़े देश की प्रति व्यक्ति आय के करीब भी नहीं पहुंच सके हैं।

हमारे बराबर जो देश खड़े हैं, उनमें बांग्लादेश (1211.7), कैमरून (1280) घाना (1381), केन्या (1376), पाकिस्तान (1429) और सब सहारा अफ्रीका (1571) ही हैं। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग 1800 डॉलर है। यह शर्मनाक स्थिति नहीं तो क्या है? अब जरा इन बडे देशों की प्रति व्यक्ति आय देखिए– आस्ट्रेलिया (56327.7), कनाडा (43248), फ्रांस (36248), स्वीडन (50272.9), स्वीटजरलैंड (80214), यूनाइटेड किंग्डम (43734) और अमरीका (55836) डॉलर प्रति व्यक्ति, ये हमसे कितने आगे हैं।

अब यह तय करना मुश्किल नहीं है कि उदारीकरण का फायदा भारत को कितना मिला है और भारत की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था में यहां के नागरिकों को कितना लाभ पहुंचा है? देश में जब उदारीकरण की बयार चली, तो वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर चुकी थी। तब हमारे पास बमुश्किल तीन सप्ताह के आयात बिल के लिए उपयुक्त विदेशी मुद्रा का भंडार था, केवल 1.2 अरब डॉलर का।

तब हमारी कुल अर्थव्यवस्था का आकार भी 278.4 अरब डालर का था और हमार प्रति व्यक्ति आय केवल 310 अमरीकी डॉलर थी।

आज हम अपनी स्थिति देखते हैं तो बहुत गर्व होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 2 खरब डॉल से भी अधिक है, हमारे पास इस समय 364 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और हमारी प्रतिव्यक्ति आय 1800 डॉलर है। यानी हम देखे तो 25 साल में हमारी

अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय लगभग छह गुणी बढ़ गई है। यह खुश होने की बात है। पर यह खुशी तब काफूर हो जाती है जब इन्हीं आकड़ों की तुलना अन्य समकक्षी देशों से करते हैं।

इस 25 साल में हमारे सामाजिक ढ़ांचे पर खड़ी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। परस्पर सहयोग के भाव से चल रही ग्रामीण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है।

स्वरोजगार के अवसर, जिसमें खेती और उससे जुड़े व्यवसाय प्रमुख रूप से शामिल थे गायब हो गए हैं और उनकी जगह लेबर यानी मजूदर शब्द ने पैर जमा लिए हैं।

देश के प्राकृतिक संसाधन का, बर्बादी की सीमा तक दोहन कर लिया गया है और 50 साल से लोगों के खून पसीने से खड़े अधिकतर सार्वजनिक उद्यम या तो बेच दिए गए या बंद कर दिए गए हैं।

उदारीकरण में निजी लाभ पर कोई रोक टोक नहीं होने के कारण महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई है। और सबसे प्रमुख बात कि इस 25 साल में विदेशी कंपनियों ने जितने लाभ इस देश से लूट खसूट कर अपने देश भेजे उतने ब्रिटिश शासन में भी कभी नहीं लूटे गए। यदि इन आकड़ों को ग्रामीण भारत के संदर्भ में देखे तो स्थिति बेहद दयनीय नजर आती है।

हाल ही में सरकार द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार 75 फीसदी ग्रामीण परिवार अपना जीवन 79 डॉलर यानी लगभग 5000 रुपये से कम में व्यतीत करता है और इनमें से 28 फीसदी यानी लगभग पांच करोड़ परिवार के पास संचार के कोई साधन नहीं हैं।

सात करोड़ ग्रामीण परिवार सामाजिक सुरक्षा की सुविधाओं से वंचित है। अब क्या यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि ग्रामीण भारत के लिए उदारीकरण का मतलब बड़ा शून्य से ज्यादा नहीं है।

लगे हाथ यह भी जान लेना आवश्यक है कि इस उदारीकरण ने खेती बाड़ी को आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बना दिया है जिसके कारण तेजी से लोग इससे दूर जाने लगे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस समय 40 करोड़ लोग खेती बाड़ी का त्याग कर शहर और कस्बों में मजदूरी के लिए भटक रहे हैं।

हमारे कृषि इनपुट बाजार पर इस समय विदेशी कंपनियों का कब्जा है उनमें स्विटरजरलैंड की सिंगेटा (18 फीसदी), जर्मनी की बेयर (17 फीसदी), जर्मनी की ही बीएएसएफ (10 फीसदी), अमरीका की मोनसेंटो (10 फीसदी), और डॉ एग्रो (9 फीसदी), प्रमुख हैं।

जितनी पूरे यूरोप ओर अमरीका की जनसंख्या है उससे बड़ा मध्य आयवर्गीय बाजार भारत का है। इसलिए उदारीकरण का सबसे अधिक फल इन्हीं बड़े देशों को मिला है।

चाहे बीज हो या कीट नाशक या कि खरपतवार नाशक सभी क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां हावी हैं।

कृषि ही क्यों जिधर देखो उधर ही विदेशी ब्रांड और उत्पाद का बोलबाला है। कंप्यूटर और अप्लीकेशंस से जुड़े व्यवसाय में आईबीएम और माइक्रोसाफ्ट का बोलबाला है तो उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय में नेस्ले और प्रॉक्टर एंड गैम्बल का।

शीतल पेय में आज भी पेप्सीको और कोकाकोला छायी हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सोनी और सैमसंग का दबदबा है तो मोबाईल फोन में एप्पल को लेकर जबर्दस्त क्रेज है। बैंकिंग में एबीएन एमरो और अमरीकन बैंक के साथ सिटी क्राप का भी नाम है।

ऑटो सेक्टर में मारूति, हुंडई, हीरो, फोर्ड और जेनरल मोटर टाटा और महिन्द्रा को जबर्दस्त टक्कर दे रहे हैं तो खान पान में मैक डोनान्ड और पिज्जा भी मजबूती से जमे हैं।

जितनी पूरे यूरोप ओर अमरीका की जनसंख्या है उससे बड़ा मध्य आयवर्गीय बाजार भारत का है। इसलिए उदारीकरण का सबसे अधिक फल इन्हीं बड़े देशों को मिला है।

1991 से आज तक यह जाने समझे या समीक्षा किए बिना ही कि उदारीकरण का लाभ वास्तव में देश के अधिकतर लोगों को मिल भी रहा है या नहीं, विकास के नाम पर अमीरों को और अमीर और गरीबों को बहुत गरीब बनाने में ही कहीं यह उदारीकरण योगदान तो नहीं कर रहा, भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाहें पसारे खड़ा है।

उदारीकरण के नाम पर हमने कृषि, बागवानी, खनन, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रसारण अपलिंकिंग, एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड, एयर पोर्ट ब्राउन फील्ड, एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं, निर्माण , इंडस्ट्रियल पार्क, थोक व्यापार, आर्थिक सलाहकार सेवाएं, फार्मा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस फील्ड को पूरी तरह विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है।

अब तो रक्षा क्षेत्र में भी शत प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है।

उद्योग से लेकर सेवा के क्षेत्र तक जहां जहां लाभकारी व्यवसाय हो सकता था, सभी पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कब्जा जमा लिया है।

यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तो सवाल यह नहीं कि किस क्षेत्र को हमने विदेशी कंपनियों के लिए खोला है, बल्कि जिज्ञासा इस बात को जानने में है कि अब कौन सा क्षेत्र है जिसे भारतीय के लिए अभी भी आरक्षित रखा गया है। ❑❑

प्रकृति की पुकार

धर्म मानव सभ्यता के उन प्रारंभिक अविष्कारों में से है, जो मानव–जीवन को सुन्दर, अनुशासित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए छुआ है। उसका हमारे जीवन के प्रत्येक उस पहलू से संबंध है जिसका मानव जीवन के अस्तित्व से सीधा संबंध है। अतः धर्म का पर्यावरण से बहुत स्वाभाविक लगाव है।

हमारी परंपरा में धर्म के साथ पर्यावरण गहरे तक गुंथा हुआ है। हमारे धर्म–ग्रंथों में प्रकृति के साथ हमारे जीवन संबंधों पर बहुत जोर दिया गया है। धर्म और संस्कृति की रक्षा से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमारे धार्मिक बाङमय में प्रकृति रक्षा, जैविक विविधता के नियमों, विधियों और पद्धतियों का अध्ययन व अनुसंधान वैज्ञानिकता के आधार पर किया गया है। वामन पुराण में कहा गया है कि प्राकृतिक परिवेश में संतुलन एवं प्राकृतिक तत्वों में नैसर्गिक विशिष्टता जब तक बची रहेगी तब तक ही मानव कल्याण सुरक्षित है। स्मृतियों, हिन्दू धर्म ग्रंथों व पुराणों में जगह–जगह पर जीव–जंतु, वनस्पतियों एवं मानव के जीवन क्रम का विकास दर्शन पर्यावर्णीय चेतना से विमुक्त नहीं है और इनके पोषण संवर्धन एवं संरक्षण के लिए इस साहित्य में जोर दिया गया है। जैव मंडल तथा परिस्थितिकी असंतुलन से उत्पन्न होने वाले संकट से बचाव हेतु उपायों से धर्म–ग्रंथ भरे पड़े है। आवश्यकता है उसे अपनी शिक्षा और समाज व्यवस्था में पूर्णतः स्वीकार करने की, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों में यही भाव उत्पन्न हो सके।

धर्म और संस्कति की रक्षा से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्योंकि हमारे धार्मिक बाङमय में प्रकति रक्षा, जैविक विविधता के नियमों, विधियों और पद्धतियों का अध्ययन व अनुसंधान वैज्ञानिकता के आधार पर किया गया है। वामन पुराण में कहा गया है कि प्राकतिक परिवेश में संतुलन एवं प्राकतिक तत्वों में नैसर्गिक विशिष्टता जब तक बची रहेगी तब तक ही मानव कल्याण सुरक्षित है।

– रेणु पुराणिक

जैन तत्व दर्शन में भी पृथ्वी पर पाये जाने वाली वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु अहिंसात्मक विचारधारा का प्रबल समर्थन मिलता है। यह अहिंसा मानव मात्र में अहिंसक विचार एवं मैत्रीपूर्ण जीवन व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार का निर्माण करता है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में वर्णित पर्यावरणीय चेतना के अनुसार प्राकृतिक साधन जितने स्वच्छ और निर्मल होगें, हमारे शरीर और मन उतने ही स्वच्छ और स्वस्थ होंगे। बुद्ध नियमावलनी के अनुसार मानवीय प्रकृति और बाह्य दोनों पर्यावरण कार्यकरण नियम के अनुसार प्रतिबद्ध है।

बौद्ध संघ पर्यावरण के विषय में इतने धार्मिक तथा सतर्क थे कि संघ में वृक्ष के नीचे ठहरने का प्रावधान स्वीकृत किया थाॅ संयुक्त निकाय में अरण्यक होने की प्रशंसा की गई है।

वेद कहते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना है तो उसके पर्यावरण को बचाओ। सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, पेड़–पौधों, जड़–चेतन, सभी पर्यावरण के घटक है। प्राचीन वेदों में हमारे शरीर को भी पांच पर्यावरणीय घटकों से मिलकर निर्मित माना है, तथा कहा है कि ''क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा – पंच तत्व ये अधम शरीरा''। वेदों ने इन घटकों को देव कहा है। देव अर्थात् ''दिव्य गुणंसमन्वितम''। प्राचीन काल से ही हमारे देश में इन प्राकृतिक घटकों को शुद्ध–स्वच्छ रखकर पर्यावरण संरक्षण की परंपरा विकसित की गई थी। पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से रीतियां, रूढ़ियां और अनुष्ठानों की परंपरा स्थापित की गई थी। वास्तव में हमारे विचार और आचार आज के आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के सम्मत है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रदूषण कम करना है तो वृक्ष लगाओ, तो हमारों वर्ष प्राचीन हमारा दर्शन इन्हें पूजनीय घोषित कर इनको नष्ट करने की संभावना की समाप्त कर देता है। हमारे वैदिक मनीषियों ने वनस्पति, औषधि, लता और वनों का महत्व समझाते हुए इन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हुए यजुर्वेद में कहा ''नमो वृक्षेभ्य''। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद तो प्रकृति की वंदना पर ही केंद्रित है।

महाभारत में एक वृक्ष दस पुत्रों के समान माना गया है। हमारे ग्रंथों में प्रत्येक वृक्ष को देवताओं के साथ जोड़कर उनके संरक्षण का अनुठा प्रयास किया है। जैसे, पीपल–भगवान विष्णु, वट–ब्रह्मा और विष्णु, तुलसी–लक्ष्मी विष्णु, पत्थर वेल–शिव, नीम–शीतला, अशोक–इन्द्र, आंवला–विष्णु स्वरूप में स्वीकार किये गये है। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों में इन वृक्षों को देव रूप मानने का विवरण आस्था से जोड़ने का आशय इनके संरक्षण में निहित है। उदाहरणतः पीपल ऐसा वृक्ष है जो चौबीस घंटे ऑक्सीजन देता है और उसकी तुलना में अधिक कार्बन सोखता है।

प्रकृति के संवर्द्धन में पारिवारिक उत्सव को पर्यावरण संरक्षण में जोड़ सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कडी के रूप में परिवारजनों का जन्मदिन हो या अन्य शुभ कार्य वृक्षारोपन कर पृथ्वी के उस ऋण की मुक्ति को रास्ता भी निकाल सकते है जिसमें हमने जो कुछ पृथ्वी से लिया है या लेंगे, उसकी वापसी का रास्ता बन सके और इससे पृथ्वी को नुकसान भी नहीं पहुंचे। इसके द्वारा प्रकृति प्रेम पनपेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार भी तैयार होंगे। इसी प्रकार परिवार के अन्य कार्यों जैसे शादी–ब्याह, मुंडन, नामकरण, जन्मदिन तथा पावन पर्वों पर वृक्षारोपन करके इन्हें पर्यावरण के साथ जोड़ लेना चाहिए। ऐसा करके शायद हम प्रकृति बचा पायेंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं का हिस्सा बना पायेंगे।

इतिहास को खंगाले तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा में हमेशा महिलाएं अग्रणीय रही है। विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की प्रेणता गौरा देवी जिनकी वन–वृक्ष की लड़ाई विश्व प्रसिद्ध है, आखिर पूरे हिमालय में वनों के प्रति संवेदनशीलता एवं वनों के पतन की पीड़ा उन्हें ही क्यों हुई? बात गौरा दौरा देवी की ही नहीं बल्कि राजस्थान के विश्नोई समुदाय की अमृता देवी (इमरती देवी) की भी है जिन्होंने महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपककर उनके काटने का विरोध किया और अपना बलिदान किया। इस आंदोलन में 69 महिलाएं और 293 पुरूष शहीद हुए थे। इसी प्रकार नोबल पुरस्कार विजेता अफ्रीका की मथाई को अनेकानेक वृक्षों को लगाने की धुन सवार हुई। अतः इतिहास साक्षी है कि वनों में वृक्षों को लगाने की बात हो या इनको संरक्षण के साथ बचाने की, महिलाएं हमेशा से ही अग्रणी रही है।

वास्तव में वृक्ष और महिलाएं समान प्रवृत्तियां रखती हैं। दोनों ही समाज के लिए समर्पित है। दोनों का समाज में समान व्यवहार है। महिला और वृक्ष समाज के सृजन और संवर्द्धन की बेहतरी के लिए बिना किसी शर्त के सदियों से सेवा में संलग्न है। निस्वार्थता दोनों का मूल चरित्र है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि दोनों के बिना प्रकृति व पृथ्वी तथा समाज अर्थविहीन और पंगु बन कर रह जायेगा। सच यह है कि मूल भाव से दोनों ही एक–दूसरे को समझते ही नहीं बल्कि पूरक भी है। क्योंकि महिलाएं वनों एवं वृक्षों से अधिक तालमेल रखती है। यह स्वतः ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रकृति और प्रवृत्ति की समान झलक मिलती है।

भौतिकता और हमारी जीवन शैली में बढ़ते पश्चिती जीवन के प्रभाव की वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे है। फिर भी हमारे धर्म ने पेड़–पौधों के संरक्षण और संवर्द्धन द्वारा हमें प्रकृति से गहरे तक जोड़ रखा है। पेड़–पौधों के संरक्षण और पूजन के साथ–साथ परिस्थितिकी संतुलन के लिए पशु–पक्षियों का हमारी परंपराओं और अनुष्ठानों में समावेश तथा नदी–पहाड़ के प्रति संवेदनशीलता हमें हमारे धर्म और परंपराओं से ही प्राप्त हुई है।

वर्तमान की दौड भरी जिंदगी में हम न केवल खुद से दूर हो रहे हैं, बल्कि हमारा प्रकृति से नाता भी टूटता जा रहा है। यही समय है प्रकृति को सहेजने, संवारने और संरक्षित करने का। शायद यह स्वयं उस धरा की पुकार है कि उसका दोहन नहीं रूका तो आने वाली हमारी पीढ़ियां उसकी प्रत्येक देन को पाने के लिए तरसेगी। ❑❑

लेखिका स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय महिला प्रमुख है।

सामाजिक समरसता के प्रणेता

माननीय बाला साहब देवरस

(जन्मशताब्दी वर्ष 2015–16 के संदर्भ में)

बाला साहब के साधारण व्यक्तित्व में प्रखर विचार छुपा हुआ था। वे समाज में व्याप्त प्रत्येक रूढ़ी को समाप्त करना चाहते थे। इसका व्यवहार उन्होंने अपने घर से प्रारंभ किया। शुद्र जाति के स्वयंसेवकों को उन्होंने अपने साथ चौके में ही भोज

– **डॉ. विजय वशिष्ठ**

बाला साहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक थे। श्री देवरस सामाजिक समरसत्ता के प्रणेता थे। उनका यह उद्घोष ''अस्पृश्यता गलत नहीं तो कुछ गलत नहीं।'' बहुत प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा हिन्दू समाज में कभी वर्ण व्यवस्था रही होगी। लेकिन वर्ण के आधार पर कोई नीच अथवा महान नहीं हो सकता। जन्म से अर्थात् आनुवंशिकता से गुण–संपदा आती है, इस प्रकार का विचार पूर्वजों ने किया, किन्तु उस काल में भी उन्होंने जन्मतः आने वाले गुणों की मर्यादा को समझा, इसलिए कहा–

''शूदोऽपि शील सम्पन्नो, गुणवान ब्राह्मणों भवेत्।
ब्राह्मणोऽपि क्रियाहीनः शूद्रात प्रत्यवरो भवेत्।।

अर्थात् शूद्र भी यदि शीलवान और गुणवान हो तो वह ब्राह्मण बन जाता है तथा ब्राह्मण यदि कर्महीन हो जाये तो वह शूद्र से भी नीच है। इसी प्रकार ''जात्या ब्राह्मण इति चेतन्'' अर्थात जन्म से ब्राह्मण होता है, ऐसा कहना उचित नहीं।

यह वर्ष बाला साहब देवरस का जन्म शताब्दी वर्ष है। माननीय बाला साहब का जन्म 11 दिसंबर 1915 को महाराष्ट्र के भण्डारा जिले के आम गांव में एक वेदपाठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे पांच भाई और चार बहिनों में चौथे थे। उनका पूरा नाम मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बाला साहब देवरस) था। 1927 में उन्होंने ग्यारह वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश लिया।

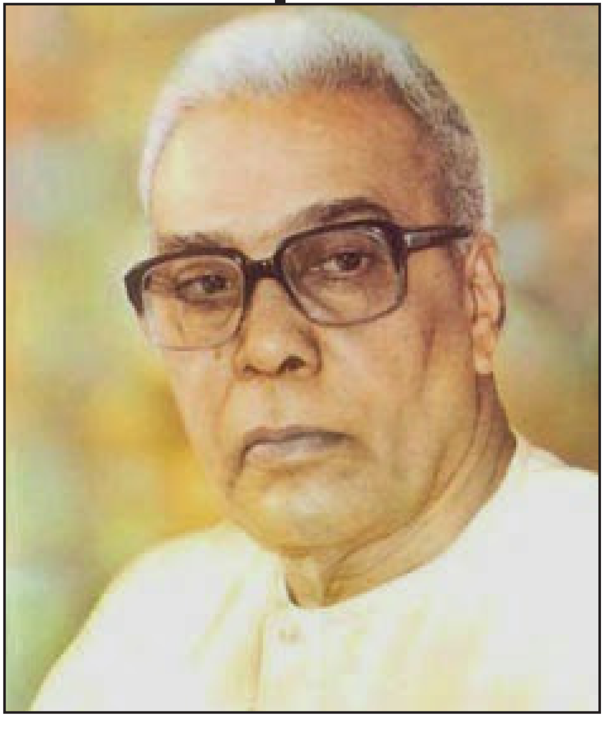

1931 में न्यू इंगलिश हाईस्कूल नागपुर से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1935 में बी.ए. एवं 1937 में एल.एल. बी. परीक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। 1946–47 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह बने। 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा। वे 3–4 माह जेल में रहे। 1965 में वे सरकार्यवाह बने। इस दायित्व को उन्होंने 1973 में सरसंघचालक बनने तक निभाया। परम् पूज्य श्री गुरूजी के देहावसान के पश्चात् 1973 में सरसंघचालक बने। 1994 में उन्होंने स्वयं इस दायित्व से निवृत्ति की घोषणा की। 21 वर्ष तक सरसंघचालक के दायित्व का निर्वहन किया। 1996 में 17 जून को पुणे में उनका देहावसान हो गया।

प्रखर बुद्धि – बाला साहब के साधारण व्यक्तित्व में प्रखर विचार छुपा हुआ था। वे समाज में व्याप्त प्रत्येक रूढ़ी को समाप्त करना चाहते थे। इसका व्यवहार उन्होंने अपने घर से प्रारंभ किया। शुद्र जाति के स्वयंसेवकों को उन्होंने अपने साथ चौके में ही भोजन कराया। उनका कहना था कि हम सब एक भारत मां की संतान हैं, अतः भेदभाव कैसा। इसीलिए उन्होंने

पूना में एक व्याख्यान में कहा था कि *''यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है।''*

व्यापक हिन्दूत्व का विचारः बाला साहब का हिन्दूत्व का विचार व्यापक था, उन्होंने कहा हिन्दू जीवन धारा ही इस राष्ट्र की मुख्यधारा है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुसलमान और ईसाई अपनी उपासना पद्धति बदलें। मुसलमान अपनी मस्जिद में जायें और कुरान पढ़ें, ईसाई चर्च में जायें और बाईबल पढ़ें। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम यहां के सांस्कृतिक प्रवाह के अंग हैं, इसी प्रकार की उनकी मनोभूमिका चाहिए। दुर्देव से यह मनोभूमिका नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम अलग हैं, यह भाव नहीं चाहिए। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रवादी होना चाहिए, पृथकतावादी, अलगाववादी या आतंकवादी नहीं।

अस्पृश्यता का घोर विरोधः बाला साहब देवरस अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। पूना में बसंत व्याख्यान माला में 8 मई 1974 को उन्होंने कहा अस्पृश्यता अपने समाज की विषमता का एक अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यजनक पहलू है। विचारशील लोगों का मत है कि अति प्राचीनकाल में भी इसका अस्तित्व नहीं था तथा काल प्रवाह में यह किसी अनाहूत की भांति समाविष्ट होकर रूढ़ी बन गयी। वास्तविकता कुछ भी हो, किन्तु हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि अस्पृश्यता एक भयंकर भूल है और इसका पूर्णतया उन्मूलन आवश्यक है। (Lock, Stock and Barrel) इस संबंध में अब कहीं भी दो मत नहीं है। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के संबंध में कहा था कि "If slavery is not wrong then nothing is wrong" इसी तरह हमें भी यह कहना है कि "If untouchability is not wrong then nothing is wrong" यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। हमारा दायित्व है कि समाज में सौहाद्र, सामंजस्य एवं परस्पर सहयोग का वातावरण स्थापित हो – इसके लिए जरूरी है कि हम सबके साथ समरसत्ता का भाव रखें, इस व्यवहार को अपने व्यक्तिगत जीवन से प्रारंभ करें। संघ की शाखाओं में यह कार्य स्वाभाविक रूप से होता है। हमारे घरों एवं सामाजिक व्यवहार में यह भाव दिखना चाहिए।

आज मीड़िया के बंधुओं को भी यह सोचना होगा कि वे हिन्दुओं के आपसी राजनैतिक अथवा व्यक्तिगत झगड़ों को जातिवादी संघर्ष का शीर्षक न दें। यह कदापि उचित नहीं है। हम सभी एक ही परमात्मा के अंश है। ''आत्मवत् सर्व भूतेषु'' (सभी प्राणियों को अपने समान मानना) का व्यवहार करें।

> **राज्य द्वारा किसी संप्रदाय विशेष का पोषण व विरोध दोनों ही समान रूप से घातक हैं।**

आलोचना नहीं सहयोगः बाला साहब ने कहा था कि दलित अथवा अस्पृश्य माने गये बंधुओं ने काफी अत्याचार एवं कष्ट सहन किये हैं। अतः यह अभिप्रेरित है कि अन्याय समाप्त होकर, उन्हें सबके साथ समानता का स्थान प्राप्त हो। अतः सभी लोगों को इस दृष्टि से प्रयास करने चाहिए। सभी को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि भूतकाल के झगड़ों को वर्तमान में घसीट कर अपने भविष्य को खतरे में न डाले। हम सब इसी समाज के अंग है। इसी भावना के आधार पर अपेक्षित सामाजिक समरसत्ता का वातावरण बन सकेगा। मेरी यह धारणा है कि दलित बंधु किसी की कृपा नहीं चाहते, वे संविधान में प्रदत्त बराबरी का स्थान चाहते हैं और वह भी अपने पुरूषार्थ से।

तुष्टीकरण की राजनीति का विरोधः बाला साहब तुष्टीकरण की राजनीति के विरोधी थे। उन्होंने कहा वोट और सत्ता की राजनीति में लिप्त सरकार और राजनैतिक दल की नीति के कारण कुछ समुदाय समरसत्ता एवं एकात्मता की ओर बढ़ने के स्थान पर राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर हटते जा रहे हैं। राज्य द्वारा किसी संप्रदाय विशेष का पोषण व विरोध दोनों ही समान रूप से घातक हैं। जो आगे चलकर पृथकतावाद और विघटन का कारण बनता है, इसलिए संघ इस मनोवृत्ति का विरोध करता है, हम मानते हैं कि संस्कारयुक्त, जागृत और संगठित हिन्दू समाज पर ही भारत की सर्वांगीण उन्नति निर्भर करती है। हिन्दू समाज को भारत की राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने का हमने संकल्प किया है, हम भारत को पुनः एक महान राष्ट्र बनायेंगे और डॉक्टर हेडगेवार के सपनों को साकार करेंगे।

स्वदेशी के प्रबल समर्थकः बाला साहब स्वदेशी के विचार एवं व्यवहार के प्रबल समर्थक थे। उनके कार्यकाल में ही स्वदेशी जागरण मंच का 1992 में गठन किया गया। उन्होंने 12 जनवरी 1992 को अपने संदेश में कहा ''स्वदेशी की उदात भावना स्वाधीनता संग्राम में अपने सर्वस्व की आहूति देने के लिए नवयुवकों को प्रेरणा देती रही है, लेकिन अब देश स्वतंत्र हो जाने पर इसका देशवासियों को विस्मरण होने के कारण ही आज अपने देश आर्थिक संकटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं तो अपने देश की आर्थिक स्वाधीनता ही खतरे में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। अतः हमें निश्चित करना होगा कि किसी भी विदेशी शक्ति को अपने देश के राष्ट्रीय जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। मुझे विश्वास है कि आज से देश भर में

प्रारंभ हो रहे इस आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम में प्रत्येक देशवासी अपने सभी जाति–पंथ, भाषा, प्रांत के भेद भुलाकर तथा पक्षामिनिवेश छोड़कर, आत्मीयता से व उत्साह से सम्मिलित होगा और स्वदेशी जागरण मंच के इस महान अभियान को सफल बनाने में सहायता करेगा।

वर्ष (2015–2016) पूज्य बाला साहब का जन्मशताब्दी वर्ष है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागौर (राज.) 11, 12, 13 मार्च 2016 में एक प्रस्ताव पारित कर देश के सभी नागरिकों से दैनन्दिन जीवन में समरसत्तापूर्ण व्यवहार करने का आह्वान किया है। प्रतिनिधि सभा में पारित एक प्रस्ताव में यह कहा गया कि ''प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनन्दिन जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक स्तर पर अपने इस सनातन और शाश्वत जीवन दर्शन के अनुरूप समरसत्तापूर्ण आचरण करना चाहिए। ऐसे आचरण से ही समाज से जातिभेद, अस्पृश्यता तथा परस्पर अविश्वास का वातावरण समाप्त होगा एवं तभी हम सब शोषण मुक्त, एकात्म और एकरस जीवन का अनुभव कर सकेंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघचालक मा. श्री मोहनराव भागवत का यह कथन उल्लेखनीय है कि मंदिर, कुंआ और श्मशान सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए।

मंदिर, कुंआ और श्मशान सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए।

पूज्य बाला साहब के जन्मशताब्दी वर्ष में उनको सच्ची श्रद्धांजली यहीं होगी कि हम अपने जीवन में सबके साथ आत्मीयता, सम्मान एवं समता का व्यवहार करें। गीता के छठें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं **''वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह वह मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है।''** गुरुनानक जी ने भी कहा है – **''एक नूर से सब जग उपज्या, कौणे भले, को मन्दे''** (एक तेज से पूरे जग का निर्माण हुआ तो कौन बड़ा और कौन छोटा) इस भाव से दैनन्दिन व्यवहार करें, तो हमारा यह महान राष्ट्र पुनः एकात्म, समृद्ध एवं अजेय राष्ट्र्य बनेगा। यह निश्चित है। आज समाज में जो कटुता एवं भेदभाव दिखायी दे रहा है इसे मिटाने के लिए भी यह आवश्यक है कि हम अपने दलित एवं वनवासी भाई–बहनों को गले गलायें तथा उन्हें राष्ट्र की विकास ही धारा में समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर दें। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीध्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जलाशयों की गाद हटाने में बाढ़ का उपयोग

बाँधों के विशाल जलाशयों की गाद को कुदरती तरीके से निकाला जा सकता है। यह चमत्कार भी नहीं है। यह सुनकर या पढ़कर भले ही अटपटा लगे पर यह संभव है। चीन ने इसे बिना मानवीय श्रम या धन खर्च किये कर दिखाया है। यह किसी भी देश में हो सकता है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। परिणाम पाने के लिये बरसात के चरित्र, जलस्रोत से पानी निकालने वाली व्यवस्था के इंजीनियरिंग पक्ष जैसे कुछ पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

जलाशय के लबालब भरने और गाद निकालने के साथ–साथ बारिश के टाइम–टेबल अर्थात मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर भी पूरा–पूरा ध्यान देना होगा। इस काम का सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी है। जलाशय में पानी की उपलब्धता का असर किसान की माली हालत और कृषि उत्पादन पर पड़ता है।

दैनिक भास्कर (भोपाल संस्करण, 30 जून, 2016, पेज 14) में बाँध से गाद को निकालने के प्राकृतिक तरीके के बारे में समाचार छपा है। समाचार का लब्बोलुआब यह है कि चीन की यलो नदी मिट्टी और गाद से भरी हुई है। हैनान में यलो नदी पर शियाओलेंगडी बाँध बना है। समाचार में बताया है कि शियाओलेंगडी बाँध के गेट खोले गए। हर साल बारिश के मौसम में गेट खोले जाते हैं। इसे देखने के लिये हजारों पर्यटक एकत्रित होते हैं। गेट खोलने से गाद मिला पानी बाहर आता है।

जलाशय की गाद को यथाशक्ति कम करता है। यह आशा की किरण है। जलाशय से अधिक–से–अधिक गाद कैसे निकले और उसका टाइम–टेबिल क्या हो, तकनीकी लोग बैठकर तय कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया को यथाशक्ति निरापद बना सकते हैं।

यह अभिनव प्रयोग है। कुदरती है। हानिरहित है। पानी की गुणवत्ता को ठीक करने वाला है। इस विधि में बाढ़ के साथ आने वाली और बाँध में जमा गाद का कुछ हिस्सा बिना

जलाशय के लबालब भरने और गाद निकालने के साथ–साथ बारिश के टाइम–टेबल अर्थात मौसम विभाग की भविष्यवाणियों पर भी पूरा–पूरा ध्यान देना होगा। इस काम का सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी है। जलाशय में पानी की उपलब्धता का असर किसान की माली हालत और कषि उत्पादन पर पड़ता है।

– कष्ण गोपाल 'व्यास'

कुछ धन खर्च किये निकाला जा सकता है। यह नदी की कुदरती जिम्मेदारी को पूरा करता वैज्ञानिक तरीका है। इसी तरीके से नदियाँ, हर साल करोड़ों टन सिल्ट, चुपचाप समुद्र में पहुँचा देती हैं।

इस सिद्धांत में कोई खोट या तकनीकी कमी नहीं है। इस तरीके को अपनाने से जलाशय में जमा गंदगी कम होती है। गाद के निपटान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। मानव श्रम, ऊर्जा और धन को अन्य उत्पादक कामों में लगाया जा सकता है। विकास की योजना संचालित की जा सकती है। उपर्युक्त कारणों से चीन का अभिनव प्रयोग नजरे इनायत की अपेक्षा करता है।

पुराने समय में भारत में, बहुत सारे तालाबों का निर्माण हुआ था। कुछ तालाब हजार साल से भी अधिक पुराने हैं। विभिन्न कारणों से अधिकांश पुराने तालाब में गाद भर गई है। गाद भर जाने के कारण वे आंशिक या पूरी तरह अनुपयोगी हो गए हैं। उनके अलावा देश में बहुत बड़ी मात्रा में बाँधों, स्टापडैमों और तालाबों का निर्माण हुआ है।

अनुमान है कि अकेले मनरेगा की ही मदद से देश में 123 लाख जल संरचनाएँ बनी हैं। विभिन्न कारणों से उन सभी सतही जलस्रोतों में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो रही है। गाद जमा होने के कारण, उनकी जलक्षमता और उम्र घट रही है। कुछ छोटे तथा मंझोले सतही जलस्रोत तथा स्टापडैम गाद से पटकर लगभग अनुपयोगी हो गए हैं।

भारत में ग्रामीण तालाबों से गाद निकालने की पुरानी परंपरा रही है। उस गाद का उपयोग घर की मरम्मत तथा खेतों को उपजाऊ बनाने में किया जाता था। अंग्रेजों के भारत में काबिज होने के बाद, समाज द्वारा स्वेच्छा से गाद निकालने की परंपरा घटी। धीरे–धीरे तालाब, गाद जमाव के शिकार होने लगे। अब लोगों का ध्यान उनकी ओर गया है।

गाद निकालने के काम को धीरे–धीरे वरीयता मिल रही है। उसके लिये प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। यह काम मजदूर लगाकर या मशीनों की मदद से होने भी लगा है। अनुभव बताता है कि मौजूदा तरीका खर्चीला और अस्थायी है। इसके बावजूद देश के अनेक इलाकों में तालाबों से गाद निकालने के काम को किया जा रहा है।

तेलंगाना में इसे मिशन मोड में मिशन काकतीय का नाम देकर किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत 45000 तालाबों को पुनः जीवित किया जाएगा। इस काम पर 20,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। गौरतलब है कि तेलंगाना में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाए बहुत सारे तालाब हैं।

भारत में ग्रामीण तालाबों से गाद निकालने की पुरानी परंपरा रही है। उस गाद का उपयोग घर की मरम्मत तथा खेतों को उपजाऊ बनाने में किया जाता था।

टाइम्स आफ इण्डिया की 31 मई, 2016 को छपी रिपोर्ट के अनुसार 2.8 करोड़ ट्रैक्टर फेरों द्वारा 7.3 करोड़ घन मीटर सिल्ट निकाली जा चुकी है। सरकार ने काकतीय योजना को दिये जाने वाले दान में आयकर की छूट घोषित की है। इस अभियान को भारत सरकार के नीति आयोग ने बहुत अच्छी पहल माना है। अखबार कहता है कि यह मिशन धीरे–धीरे समाज का कार्यक्रम बन रहा है। लोग स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं। यथाशक्ति दान दे रहे हैं।

चीन का प्रयोग अभिनव है। उसे भारत में भी आजमाया जा सकता है। बड़े जलाशयों में माकूल डिजाइन के अभाव में गाद निकासी का काम कठिन हो सकता है। यदि उसे सिद्धांततः मान्यता मिलती है तो भी, जल निकासी की मौजूदा व्यवस्था के आगे जाकर, प्रस्तावित तकनीकी पक्ष पर पर्याप्त चिंतन मनन आवश्यक होगा। गाद की भरपूर निकासी के लिये कुछ नया करना पड़े।

जलाशय के पानी के स्टाक का आवश्यकता से तालमेल बिठाकर ही यह काम करना होगा। चीन की नजीर और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली तेज बारिश की संभावना के कारण यह सुझाव विचार योग्य लगता है। जहाँ तक पुराने परंपरागत तालाबों और ग्रामीण इलाकों में बने छोटे–छोटे तालाबों का प्रश्न है तो उन्हें आसानी से गादमुक्त कराया जा सकता है। उनमें लगने वाली इंजीनियरिंग आसान है। यही उचित समय भी है। इस कारण सारा मामला समाज की इच्छाशक्ति का है।

कई बार गाद निपटान समस्या बनता है। यह समस्या उसकी विशाल मात्रा या गलत निपटान के कारण भी होता है। उसके अवैज्ञानिक निपटान के कारण वह एक दो बरसात के बाद तालाब में वापिस आ जाती है। उस पर किया खर्च बेकार चला जाता है। विभिन्न कारणों से कुछ इलाकों के तालाबों की गाद में हानिकारक रसायनों, भारी धातुओं और गंदगी की मौजूदगी की संभावना होती है।

ऐसी गाद से खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। उत्पादों में हानिकारक रसायनों के अंश मिलने के कारण वे मानवीय सेहत के लिये ठीक नहीं होते। इन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि चीन का प्रयोग काफी हद तक अनुकरणीय है। इसे आजमाया जाना चाहिए। ❑❑

साभारः *hindi.indiawaterportal.org*

'अमृतं वै आपः'-अमृत देने वाला जल

जल के अभाव में पोषण और जीवनयापन संबंधी सभी आंतरिक प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। यदि शारीरिक जल की मात्र में 10 प्रतिशत की कमी हो जाये तो निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। विशेषकर बच्चों में यदि 20 प्रतिशत की कमी हो जाए तो मत्यु हो जाती है। – **वैद्या हेतल एच. दवे**

जल हमारे शारीरिक वजन का लगभग 65 प्रतिशत भाग बनाता है। शारीरिक गठन में इसका इतना अधिक परिमाण में भागीदार बनना स्वयं यह सिद्ध करता है कि हमारे शरीर में इसका बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। बिना भोजन हम शायद 60–70 दिनों तक जीवित रह पायें और भिन्न–भिन्न आवश्यक पोषक तत्त्वों के अभाव में शायद कई महिनों या वर्षों तक; परंतु जल के अभाव में हम दो या तीन दिन से अधिक रह ही नहीं पायेंगे। क्योंकि जल स्वयं आवश्यक पोषक होने के साथ–साथ सभी पोषक तत्वों का वहन भी करता है। रक्त का 80 प्रतिशत अंश जल से बना होने से यह रक्त परिसंचरण में भी सहायक होता है। ऑक्सीजन व पोषक तत्त्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने और चयापचय (मैटाबोलिक) प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सभी विकारयुक्त पदार्थों को उत्सर्जित कराने में सक्षम होता है। अतः जल के अभाव में पोषण और जीवनयापन संबंधी सभी आंतरिक प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। यदि शारीरिक जल की मात्रा में 10 प्रतिशत की कमी हो जाये तो निर्जलीकरण की स्थिति बन जाती है। विशेषकर बच्चों में यदि 20 प्रतिशत की कमी हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। अगर शरीर से जल का निष्कासन प्राकृत स्वरूप में न हो तो वह शरीर की कोशिकाओं में जमा होने लगता है। 10 प्रतिशत से अधिक जल जमा हो तो सूजन की स्थिति बन जाती है। जल के आभ्यांतरिक प्रयोग से बहुत सारे रोगों को आसानी से दूर कर सकते हैं। नियमपूर्वक जल के आभ्यांतरिक प्रयोग से शरीर के सभी अंग अवयव सुदृढ़, स्वस्थ एवं निर्मल बनते हैं। अपना स्वाभाविक कार्य सुचारु रूप से करने लगते हैं। जिससे रोग शरीर में टिकने नहीं पाते। आयुर्वेद में जल ग्रहण करना व जल ग्रहण न करना अर्थात् तृषार्त रहना–प्यास के वेग को धारण करना, दोनों ही एक चिकित्सा के उपक्रम के रूप में वर्णित किए गए हैं। आयुर्वेद मतानुसार शरीरस्थ जल धातु का प्रमाण दस अंजलि बताया गया है। जल का उपयोग मिश्र, चीन, यूनान तथा भारत में ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व भी रोग निवारण तथा स्वास्थ्य संवर्धन में लोग करते थे। अरब देशों में भी जल चिकित्सा विभिन्न प्रकार के ज्वर को दूर करने में एवं चेचक रोग में विशेष रूप से की जाती है। औषधि जगत के जनक हिपोक्रैट्स भी जल चिकित्सा के प्रयोग पर बल देते थे। आज भी उनके अनुयायी जल चिकित्सा के विभिन्न रूपों जैसे स्पंजबाथ, बर्फ की थैली आदि का प्रयोग करते

हैं। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में जल चिकित्सा का उल्लेख अकाट्य प्रमाण के रूप में मिलता है यथा–'जल ही औषधि है, जल में रोगनाशक एवं अमर बना देने की अभूतपूर्व शक्ति छिपी है, जल ही परम औषधि है, रोगों का नाश करने वाला जल ही है, अतएवं यह जल तुम्हारा भी असाध्य रोग दूर करे।' **चरकसंहिता** में महर्षि चरक ने बताया है कि जल श्रेष्ठ आश्वासकर व आप्यायनकर (Encouraging & strengthening medicine) है। इसलिए ही प्राचीन भारतीय परंपरा से लेकर आज तक घर पर आए हुए आगंतुक या अतिथि को सर्वप्रथम जलपान कराये जाने का प्रचलन हैं।

जल का निषेध कितना भी क्यों न हो फिर भी पूर्णरूप से जलपान का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल के अभाव में मुखशोष तथा शिथिलता इत्यादि उपद्रव शुरु हो जाते हैं। जल का सर्वथा परित्याग करने पर मृत्यु भी हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि–**'अमृतं वै आपः'** अर्थात् अमृत देने वाला जल ही है। वास्तव में जल का संबंध जीवन के प्रादुर्भाव से लेकर लय तक होता है। इसलिये तो संस्कृत में जल का एक पर्याय जीवन बताया गया है।

जल के आंतरिक प्रयोग का उत्तम प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, अपितु उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बन जाता है। अर्थात् मन को शांति, स्फूर्ति एवं प्रफुल्लता प्राप्त होती है। मानव पाशविक प्रवृत्तियों से दूर हटकर दैवी प्रवृत्तियों की ओर जाने लगता है। दुराचार को त्याग कर सदाचार को अपनाने लगता है। जल जैसे बाह्य जगत में प्रत्येक स्थान पर कार्य करता है वैसे ही शरीर के भीतर भी कार्य करता है। अर्थात् वह शरीर में उपस्थित दूषित द्रव्यों को घोलकर ढ़ीले करके उनको अपने साथ लेकर

जल के आंतरिक प्रयोग का उत्तम प्रभाव न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, अपितु उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बन जाता है।

शरीर के उत्सर्ग मार्गों द्वारा बाहर निकाल देता है। जल शरीर में शुद्ध और स्वच्छ रूप में प्रवेश करता है परंतु अशुद्ध और अस्वच्छ रूप में शरीर से बाहर निकलता है। यही कारण है कि जलपान को एक प्रकार का आंतरिक स्नान कहा गया है।

पाश्चात्य विख्यात प्राकृतिक चिकित्सक प्रिसनिज ने अपने बहुत रोगियों को दिन रात में बीस से चालीस गिलास तक पानी पिलाकर इस बात की परीक्षा की थी कि अधिक पानी पीने से लाभ होता है या नहीं। जिसके परिणामस्वरूप यह बात ज्ञात हुई कि इतनी अधिक मात्रा में पानी पीना शरीर के लिए अनावश्यक एवं भार स्वरूप होता है। इसका बहुत कम अंश शरीर को लाभ पहुंचाता है। शेष सब शरीर के उत्सर्ग मार्गों द्वारा व्यर्थ बाहर निकल जाता है।

अंतरिक्ष जल (आकाश से गिरने वाला जल) को **महर्षि चरक** व **सुश्रुत** दोनों ने सर्व जलों में श्रेष्ठ बताया है। यह जल सौम्य होता है, उसकी प्रकृति शीतल होती है, लघु गुण वाला व अव्यक्त रस वाला होता है। इसलिए सर्वावस्थाओं में अत्यंत हितकारी बताया गया है। इस जल में अन्य भी बहुत सारे गुण हैं जैसे जीवन के लिए अमृत समान, तृप्तिकारक, हृदय के लिए हितकारी, शरीर धारक, आश्वासजनक, थकावट, ग्लानि, प्यास, मद, मूर्च्छा, तंद्रा तथा दाह को शांत करने वाला, बुद्धिवर्धक एवं प्रसन्नता देने वाला होता है।

अंतरिक्ष जल में चूना व मैग्नेशियम के लवण नहीं होने से वह अत्यंत मृदु होता है एवं जीवाणुरहित होने से वह स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ एवं हितकारी है किंतु जहां कल–कारखाने अधिक हों वहां उनसे निकले प्रदूषण से वर्षा जल भी दूषित हो जाता है इसलिए महर्षि वाग्भट ने वर्षा आरंभ का जल अपेय माना है।

अच्छी ऋतु के विकृत जल को तथा गैर मौसम में बरसे जल को नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा जल दोषों को उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति उक्त जल का सेवन प्रमादवश कर लेता है उसे अजीर्ण, श्वास, कास, प्रतिश्याय, उदरशूल व विभिन्न प्रकार के विषमरोग शीघ्र ही हो जाते हैं। जल के इतने अच्छे गुणों के बावजूद कुछ रोगियों के लिए इसका निषेध भी किया गया है जैसे अरुचि, जुखाम, मुख से लाला स्त्राव, सूजन, मंदाग्नि, ग्रहणी, घाव, चर्मरोग, उदररोग, नेत्ररोग आदि में नहीं लेना चाहिए अथवा औषधियों से सुसंस्कृत जल अल्प मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं।

उषःपान–प्रातःकाल, शय्या त्यागते ही बिना शौचादि क्रिया किए, जो पानी पिया जाए उसे उषःपान कहते हैं, जिसे नित्य पीने से शरीर संपूर्ण विकारों से रहित हो जाता है। विशुद्ध ताम्रपात्र में रखा हुआ जल 12 घंटे में शुद्ध होकर स्वास्थ्यवर्द्धक गुणों से युक्त हो जाता

है। तांबे के पात्र में उषःपान को अमृतपान के समान कहा गया है जिससे कोष्ठ की शुद्धि होती है, पित्तजनित रोग नहीं होते एवं रक्त शुद्धि होकर हृदय, मस्तिष्क व स्नायुमण्डल को बल मिलता है। कहा गया है कि सूर्योदय के समय आठ अंजलि जल पीने से मनुष्य कभी रोगी नहीं होता, बुढ़ापा नहीं सताता और सौ वर्षों से पूर्व नहीं मरता।

कुल्ली करना (हलक–नहान)– मुंह में सादा पानी भरकर उसे तब तक हिलाते रहिए जब तक वह गर्म न हो जाए, तत्पश्चात् मुंह से निकाल दीजिए। हर समय एक या डेढ़ मिनट तक मुंह में पानी रखकर उसे हिलाने–डुलाने से पानी गर्म हो जाता है। अगर मुंह के घाव आदि के कारण पानी को हिलाने डुलाने में असुविधा हो तो कुछ देर तक मुंह में ही पानी रखकर निकाल देने से भी लाभ मिलता है। इस क्रिया से गले के उपर की पीड़ा, शिरःशूल, कर्णशूल, दंतशूल, मुख के छाले या घाव, नेत्र पीड़ा आदि शांत हो जाती है।

काम के समय जलपान– हमारे **वेदों** की भी यही आज्ञा है कि–**'अपो शान कर्म करु'** अर्थात् जब कार्य में संलग्न हो तो जलपान करो। जब भी हम किसी भी कार्य में संलग्न होते हैं तो हमारे शरीर की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति उसमें व्यय होती है। इस व्यय की गई शक्ति को पुनः अर्जित करने के लिए व कार्य में दुगने उत्साह से संलग्न होने के लिए आवश्यक है कि बीच–बीच में पानी पीया जाये जिससे शरीर तरोताजा हो जाता है तथा उसमें नवशक्ति का संचार हो जाता है।

उपवास काल में जलपान– उपवास चाहे धार्मिक दृष्टि से किए जा रहें हो या चिकित्सा की दृष्टि से, उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि बीच–बीच में जल पीते रहें जिससे आंतों की सफाई के साथ–साथ पूर्ण शरीर की भी सफाई हो जाती है। उपवास काल में यदि यथेष्ट जल न पिया जाए तो वह उपवास सफल नहीं होता। इसलिए दिन में कई बार थोड़ा–थोड़ा करके खूब जल पीना चाहिए।

शीत जल के गुण– शीतल जल मूर्च्छा, पित्तजरोग, शरीर में दाह, रक्तविकार, भ्रम, क्लम, श्वास व नासागत रक्तपित्त में लाभकारी होता है। यहां शीतल जल का उपयोग पीने, स्नान करने और मुख पर छींटे आदि देने में रोगानुसार कर सकते हैं जैसे प्यास में शीतल जल पीना, मूर्च्छा में नेत्रों पर छींटे देना, मदात्यय और ग्लानि में शीतल जल का पान व स्नान करना व उष्णता में शीतल जल से स्नान व अवगाहन करना आदि।

उष्ण जल के गुण– हम जानते है कि शुद्ध जल का स्वाद अव्यक्त होता है इसलिए जिन लोगों को औषध के भिन्न–भिन्न स्वाद से अरुचि है वे लोग उष्ण जल को युक्तिपूर्वक ग्रहण करके अपने आपको लाभांवित कर सकते हैं। उष्ण जल दीपन, पाचन, कण्ठ्य, लघु, वस्तिशोधक, वायु का अनुलोमन करने वाला व कफ का शोषण करता है। अगर बारम्बार तृषा से पीड़ित कोई व्यक्ति गर्म जल की अल्प मात्रा भी ग्रहण करे तो तृषा शांत हो जाती है। हिक्का, आध्मान्, वात विकार, कफ विकार, प्रतिश्याय, कास, श्वास व पार्श्वशूल में उष्ण जल लाभदायी होता है।

उष्ण जल निषेध –पैत्तिक विकारों में उष्ण जल का निषेध किया गया है। यद्यपि जल मधुर विपाक व शीतवीर्य होता है फिर भी उष्ण जल अधिक मात्रा में लेने पर वह पित्तकफ को बढ़ाता है और कहा भी गया है कि **'अति सर्वत्र वर्जयेत्'।**

श्रृतशीत जल के गुण– जल को काढ़े के समान उबाल कर शीतल कर लेने से वह जल हल्का हो जाता है। क्लेद या कफकारक नहीं रहता। वर्षा ऋतु में श्रृतशीत जल का प्रयोग करना चाहिए। श्रृतशीत जल जहाँ पित्त की अधिकता हो अथवा सन्निपातज रोग की स्थिति हो तो प्रयोग में लेना चाहिए। जहां जल ग्रहण करने का निषेध किया गया है उन रोगों में भी श्रृतशीत जल का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह जल दोषन, पाचक व लघु होता है। जल का अग्नि पर पकाए जाने के आधार पर भी उष्णोदक के तीन प्रकार है–यथा–अर्धावशिष्ट, पादावशिष्ट व अष्टमांशावशिष्ट जो क्रमशः वात, पित्त व कफ के विकारों में उपयोगी है।

अपने स्वास्थ्य के शुभचिंतक को कभी भी बासी जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि वह जल अम्लतायुक्त व कफ का उत्कलेश करने वाला होता है। अतएवं स्वस्थ व्यक्ति या रोगी के लिए हितकर नहीं है। प्रातःकाल का उबाला हुआ जल सायंकाल तक तथा सायंकाल का उबाला हुआ प्रातःकाल तक ही लेना चाहिए क्योंकि श्रृतशीत जल भी चार प्रहर (एक प्रहर में तीन घंटे) के अनंतर त्रिदोषकारक हो जाता है। श्रृतशीत जल त्रिदोषन होने से दाह, अतिसार, पित्त व रक्त के रोग, मूर्च्छा, तृभणा, भ्रम, मिचली में भी हितकारी है। जल को पंखे के नीचे रखकर ठंड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह से जल दुर्जर, पचने में भारी विष्टम्भी हो जाता है।

अंत में हम निम्नोक्त वेद वाक्यों से अपने जल सेवन विधान विषय पूर्ण कर आपसे उक्त निर्देशों के पालन की अपेक्षा करते हैं।

''जल ही औषधि है। जल में रोगनाशक एवं अमर बना देने की अभूतपूर्व शक्ति छिपी है। रोगों का नाश करनेवाला जल ही है। जल से अभिसिंचन करो, उपसिंचन करो, क्योंकि यह सर्वोत्तम औषधि है। इसके प्रयोगमात्र से जीवन सुखमय और शान्तिमय हो जाता है''।❑❑

लेखिका राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के प्रसूति–स्त्रीरोग विभाग में एसिस्टैंट प्रोफेसर है।

देश भर में एफडीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

जून 20, 2016 को सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, कृषि पदार्थों का विपणन, कृषि, पशुपालन, प्रतिरक्षा, सेक्यूरिटी सेवा, ब्राउन फील्ड फार्मा सहित कई क्षेत्रों में एफडीआई के लिए नियमों को शिथिल करने और निवेश की सीमा बढ़ाने के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली के उपराज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। देश भर में हुए विरोध कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री और सरकार से अपील की गई कि इन जनविरोधी फैसले को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए।

विदेशी पूंजी निवेश के निर्णय को वापिस लेने हेतु

ज्ञापन

प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

स्वदेशी जागरण मंच आपकी सरकार द्वारा 20 जून 2016 एवं इससे पूर्व के निर्णयानुसार खाद्य प्रसंस्करण, कृषि पदार्थों का विपणन, कृषि, पशुपालन, प्रतिरक्षा, सेक्यूरिटी सेवा, ब्राउन फील्ड फार्मा सहित ➜

➔अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को शिथिल करने और विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने के विरूद्ध कड़ा विरोध और क्षोभ व्यक्त करता है।

स्वदेशी जागरण मंच का यह स्पष्ट मानना है कि सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि उत्पादों (भारत में निर्मित) के विपणन में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की आड़ में वास्तव में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश को ही अनुमति दी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के चुनाव घोषणा पत्र के विरूद्ध ही नहीं है बल्कि यह छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, फल–सब्जी विक्रेताओं और छोटे दुकानदारों की रोजी–रोटी पर हमला है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यह वह क्षेत्र है, जो करोड़ों लोगों को **''जो है–जहां है–जैसा है''** के आधार पर रोजगार प्रदान करता है।

यह सर्वविदित ही है कि दवा निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है और भारत के विपन्न लोगों के लिए ही नहीं दुनिया के 200 देशों के गरीब लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराते हुए दुनिया में स्वास्थ्य रक्षक के रूप में जाना जाता है। भारत की जेनेरिक दवा कंपनियों पर दुनिया की नजर रहती है। ऐसे में 'ब्राउन फील्ड फार्मा' के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देकर आपकी सरकार ने विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को निगलने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ऐसे में भारत ही नहीं दुनिया भर के लोगों को सस्ती दवाईयां मिलने का रास्ता ही बंद होने की आशंका है।

सरकार द्वारा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के नियमों को और शिथिल करते हुए अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ आर्ट) प्रौद्योगिकी की शर्त को हटाते हुए विदेशी कपंनियों द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी कोई चर्चा न करते हुए, 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को अनुमति देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। दूसरी ओर सेक्यूरिटी सेवाओं में भी विदेशी निवेश को अनुमति देने से भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर खतरे मंडराने लगे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच सरकार के इस तर्क कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होते हैं, से सहमत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश के संसाधन बढ़ते नहीं, बल्कि उसमें पूंजी पलायन ज्यादा होता है। आंकड़े बता रहे हैं कि रायल्टी, डिविडेंट, ब्याज, वेतन इत्यादि के रूप में विदेशी मुद्रा का बर्हिगमण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कहीं ज्यादा हो गया है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में आयातों के कारण भी विदेशी मुद्रा का पलायन बढ़ता जा रहा है। 20 जून को सरकार द्वारा विदेशी निवेश के नियमों को शिथिल करने की प्रक्रिया में एकल ब्रांड खुदरा में विदेशी निवेश के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत की घरेलू खरीदी की शर्त को हटाकर, सरकार ने विदेशी कंपनियों द्वारा आयात को ओर अधिक बढ़ाने का रास्ता खोल दिया है, जिससे भारत के लघु उद्योगों को भी नुकसान पहुंचने वाला है। आपको विदित ही होगा कि विदेशी कंपनियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से ट्रांस्फर प्राईसिंग की कुटिल विधि द्वारा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा विदेशों को प्रेषित हो जाती है। ऐसे हजारों मामले पहले से ही विभागीय और न्यायालय के स्तर पर लंबित है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा विदेशों में चली जाती है, बल्कि कर चोरी का भी ये बड़ा स्रोत है। **पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन और स्वदेशी के सिद्धांत को आदर्श मानने वाली आपकी सरकार से स्वभाविक अपेक्षा है कि विदेशी निवेश संबंधी सरकार के फैसलों के व्यापक दुष्प्रभावों के मद्देनजर उन पर पुनर्विचार करेगी।**

स्वदेशी जागरण मंच, जो पिछले 25 वर्षों से कृषि, लघु और कुटीर उद्योगों, कारीगरों के रोजगार की रक्षा और आर्थिक स्वातंत्र्य को अक्षुण्ण रखने के प्रयास में निरंतर संघर्षरत है, आपसे निवेदन करता है कि –

1. खुदरा क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण में लगे लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योगों में रोजगार की सुरक्षा, भारत और विश्व में सस्ती दवाओं की उपलब्धता और देश की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध की संभावनाओं को समाप्त करने को सुनिश्चित करने हेतु, 20 जून को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनियों को शिथिल करने और निवेश की सीमा को बढ़ाने संबंधी **निर्णयों को तुरंत प्रभाव से वापिस लें।**
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सभी तथ्यों के साथ लाभ–हानि की समीक्षा करते हुए सरकार तुरंत एक **श्वेत पत्र** जारी करें।

स्वदेशी जागरण मंच

.... जिला, ... प्रांत

समाचार पत्रों की छलकियां

*संचार क्रांति के साथ लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गये हैं। मोबाईल तो जैसे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हो गया हो, हर प्रकार के संदेशों के आदान–प्रदान के लिए मोबाईल एक वरदान यंत्र हो गया है। मोबाईल का ही एक प्रमुख फीचर है–'**व्हाटसएप**'। इस एप के जरिये 24 घंटे लोग एक–दूसरे से जुड़े रहते है। कुछ तो बातें काम की होती है तो कुछ बेकाम की। यहां हम व्हाटसएप के जरिये हस्तांतरित कुछ संदेशों को उपयोगिता के आधार पर यहां प्रस्तुत कर रहे हैं –*

ज्ञान भंडार

भारतीय सीमा पर पड़ोसी देश

"बचपन में MBA किया"

ब–बंग्लादेश (4,096 किमी)
च–चीन (3,917 किमी)
प–पाकिस्तान (3,310 किमी)
न–नेपाल (1,752 किमी)
M–म्यामार (1,458 किमी)
B–भूटान (587 किमी)
A–अफगानिस्तान (80 किमी)
में एवं **किया**–(silent)

- भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? – ***कोरिया में***
- ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? – **नेपाल**
- विश्व में कुल कितने देश हैं? – **353**
- विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? – **ग्रेट ब्रिटेन**
- विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? – **अलमल्विया (इराक)**
- विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर–मस्जिद नहीं है? – **सउदी अरब**
- विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? – **प्रशांत महासागर**
- विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? – **केस्पो यनसी (रूस में)**
- विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? – **एशिया**
- विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? – **चीन की दीवार**
- विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? – **सउदी अरब**
- विश्व के किस देश में सफेद हाथी पाये जाते हैं? – **थाईलैंड**
- विश्व में सबसे अधिक वेतन किसे मिलता है? – **अमेरिकी राष्ट्रपति को**
- विश्व में किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल एक साल का होता है? – **स्विट्जरलैंड**
- विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? – **नील नदी (6648 कि.मी.)**
- विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? – **सहारा** (84,00,000 वर्ग कि.मी., अफ्रीका में)
- विश्व की सबसे मंहगी वस्तु कौन सी है? – **यूरेनियम**
- विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? – **संस्कृत**
- शाखाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? – **भारतीय स्टेट बैंक**
- विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया? – **स्विट्जरलैंड**
- विश्व का का कौन सा ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है? – **रूस**
- विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? – **टेक्सास का फोर्थ बर्थ** (अमेरिका में)
- विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? – **टोकियो**
- विश्व की लम्बी नहर कौन सी है? – **स्वेज नहर** (168 कि.मी. मिस्र में)
- विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? – **महाभारत**

....

- चीनी को जब चोट पर लगाया जाता है, दर्द तुरंत कम हो जाता है।
- बतख अपने आधे दिमाग को सुला सकती हैं जबकि उनका आधा दिमाग जगा रहता है।
- कोई भी अपने आप को सांस रोककर नही मार सकता।
- सुबह एक कप चाय की बजाए एक गिलास ठंडा पानी आपकी नींद जल्दी खोल देता है।
- फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग के पास कोई कालेज डिग्री नही है।
- अगर एक चींटी का आकार एक आदमी के बराबर हो तो वो कार से दुगुनी तेजी से दौडेगी।
- आप सोचना बंद नही कर सकते।
- चींटीयाँ कभी नही सोती।
- हाथी ही एक ऐसा जानवर है जो कूद नही सकता।
- शहद हजारों सालों तक खराब नही होता।
- समुंद्री केकडे का दिल उसके सिर में होता है।
- कुछ कीडे भोजन ना मिलने पर खुद को ही खा जाते है।
- छींकते वक्त दिल की धडकन 1 मिली सेकेंड के लिए रूक जाती है।
- हमारे शरीर में इतना लोहा होता है कि उससे 1 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है।
- बिल गेट्स 1 सेकेंड में करीब 12,000 रूपए कमाते हैं।
- आप को कभी भी ये याद नही रहेगा कि आपका सपना कहां से शुरू हुआ था।
- हर सेकेंड 100 बार आसमानी बिजली धरती पर गिरती है।
- कंगारू उल्टा नही चल सकते।
- एक गिलहरी की उमर 9 साल होती है।
- एक शुतुरमुर्ग की आँखे उसके दिमाग से बडी होती है...
- चमगादड गुफा से निकलकर हमेशा बांई तरफ मुडती है।
- ऊँट के दूध की दही नही बन सकता।
- एक कॉकरोच सिर कटने के बाद भी कई दिन तक जिवित रह सकता है।
- कोका कोला का असली रंग हरा था...
- रूपए कागज से नहीं बल्कि कपास से बनते है।

सविता वर्मा (8103237372)

रामदेव ने विदेशी कंपनियों के खिलाफ खोला मोर्चा

योग गुरु बाबा रामदेव एफएमसीजी सेक्टर में कारोबार बढ़ाने की होड़ में मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अटैकिंग मोड में हैं। उनकी कंपनी पतंजलि ने इसके लिए एक एड कैंपेन लांच किया है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों को इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। रामदेव का यह कैंपेन पीएम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना और एफडीआई पॉलिसी को झटका दे सकता है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री जेटली की हालिया नीति एफडीआई के नियमों को उदार बनाने वाली रही है।

भारत में एफएमसीजी सेक्टर की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, नेस्ले इंडिया,एशियन पेंट्स, कैडबरी इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और प्रॉक्टर एंड गैंबल शामिल हैं। वहीं पतंजलि आयुर्वेद भी शैंपू, साबुन,टूथ पेस्ट, नूडल्स, बिस्किट जैसे फूड्स, बेवेरेजेज, क्लीनिंग एजेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के जरिए एफएमसीजी में कारोबार बढ़ा रही है।

करें फ्री में अनलिमिटेड बातें

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने लैंडलाइन बिजनेस को बूस्ट करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर लेकर आया है। कंपनी अपने ग्राहकों को हर रविवार लैंडलाइन फोन से किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉल करने का ऑफर दे रही है। पूरे देश में यह सुविधा 15 अगस्त 2016 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। यह कंपनी की ओर से मौजूदा समय में दी जाने वाली नाइट स्कीम का अगला चरण माना जा रहा है। नाइट स्कीम के अंतर्गत कोई भी ग्राहक रोजाना रात को 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी भी नेटवर्क पर फ्री में बात कर सकता है।

15 अगस्त के बाद यदि कोई भी ग्राहक बीएसएनएल का कनेक्शन लेता है तो उसको महज 49 रुपए का फिक्स्ड चार्ज देना होगा और इंस्टॉलेशन का

चार्ज फ्री होगा। बीएसएनएल का नया कनेक्शन लेने पर सामान्यतः 500 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज देना होता है, जो इस प्रमोशनल ऑफर के तहत मुफ्त होगा। इसके अंतर्गत लैंडलाइन से जुड़े सभी साधारण टैरिफ प्लान, स्पेशल प्लान, कॉम्बो प्लान आदि शामिल होंगे।

महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश

मैटरनिटी बैनिफिट बिल राज्यसभा में पास हो गया। अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके कानून बनने के बाद प्राइवेट और अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की कामकाजी महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों को भी उन्हें 26 सप्ताह की लीव देनी पड़ेगी। बता दें कि कैबिनेट पहले ही मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को मंजूरी दे चुका है। सरकारी

डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला इम्प्लॉइज को पहले से ही 26 हफ्ते की मैटेरनिटी लीव मिलती है।

बैंकों की धांधली पर लगाम

बैंक की लापरवाही या असावधानी की वजह से आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड या फ्रजी बैंकिंग लेनदेन हुआ है तो इसके लिए ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही इससे होने वाले नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। प्रस्ताव के मुताबिक यदि ऐसा कोई भी लेनदेन जिसमें ग्राहक की कोई भागीदारी नहीं है और उसके साथ बैंकिंग लेनदेन में फ्रॉड हुआ है तो इसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। यदि कोई गलत बैंकिंग लेनदेन ग्राहक की गलती की वजह से हुआ है तो ग्राहक की भी

जबावदेही बनती है और इसके लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा। देश में अनाधिकृत बैंकिंग लेनदेन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आरबीआई की ओर से यह प्रस्ताव इन्ही की समीक्षा के लिए लाया गया है।

टॉप 20 में प्रेमजी एवं नाडर

तकनीकी जगत के दिग्गज दौलतमंदों में विप्रो के मुखिया अजीम प्रेमजी और एचसीएल के सह–संस्थापक

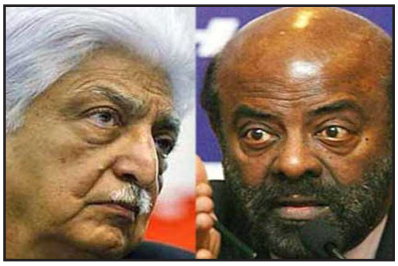

शिव नाडर ने शीर्ष 20 में जगह बनाई है। यह ताजा सूची अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने तैयार की है। इस साल की सूची में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स शीर्ष पर हैं। उनके पास 78 अरब डॉलर की संपत्ति है। प्रेमजी 16 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 13वें और नाडर 11.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 17वें पायदान पर है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दो भारतीय अमेरिकी उद्यमी भी इसमें शामिल हैं।

जीएसटी से स्टार्टअप को फायदा/नुक्सान

जीएसटी के सफलतापूर्वक लागू हो जाने के बाद देशभर के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार करना आसान हो जाएगा। जीएसटी से टैक्स संबंधी समस्याओं का समाधान होगा जिससे छोटे–बड़े सभी तरह के व्यापार को फायदा पहुंचेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। इस समय देश में कुल 4200 स्टार्टअप रजिस्टर हैं, जो 40 फीसदी की सालाना दर से बढ़ रहे हैं।

तमाम राज्यों में लगने वाले अलग अलग तरह के अप्रत्यक्ष कर टैक्स संबंधी मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में जीएसटी के माध्यम से सभी तरह के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करने से इस समस्या का समाधान होगा। स्टार्टअप के लिए टैक्स कैल्क्युलेशन आसान हो जाएगी। जीएसटी के आने के बाद कोई भी कंपनी एक केन्द्रीकृत लाइसेंस लेकर और एक सिंगल लाइसेंस फीस जमा करके किसी भी राज्य में कारोबार कर सकता है। जीएसटी में सभी बिजनेस जिनका टर्नओवर 10 लाख रुपए तक का है जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही 10 से 50 लाख तक के टर्नओवर वाले बिजनेस पर कम दर से टैक्स लगेगा। इस तरह स्टार्टअप को ज्यादा टैक्स छूट का लाभ मिल सकेगा। लॉजिस्टिक पर खर्च कम होने से स्टार्टअप का मुनाफा बढ़ जाएगा। पूरे देश में कॉमन मार्केट हो जाने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में माल का आवागमन आसान हो जाएगा। जिससे ग्राहक तक माल पहुंचाने की लागत और समय दोनों में कमी आएगी।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी के आने बाद कुछ दिक्कतें हो सकती है। मौजूदा नियम के मुताबिक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसका टर्नओवर सालाना 1.50 करोड़ रुपए से कम है उसको

किसी तरह की कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। जीएसटी के लागू होने के बाद यह लिमिट 25 लाख रुपए हो जाएगी, जो तमाम स्टार्टअप के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद खाने पीने की चीजे महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी।

मोटर व्हीकल बिल

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 को 68 संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश किया गया। इस एक्ट के बाद हिट एंड रन मामले में लोगों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

फिलहाल, यह मुआवजा 25 हजार रुपए है। इसके अलावा, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 10 हजार रुपए का जुर्माना देने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल को कैबिनेट की ओर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आम जुर्माना 100 रुपए से बढ़कर 500 रुपए होगा। वहीं, बिना लाइसेंस गाड़ी के गलत इस्तेमाल पर 1000 की जगह 5000 रुपए की पेनल्टी होगी। ओवरस्पीडिंग पर 2000 और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। नाबालिग द्वारा नियम तोड़ने पर अभिभावक या वाहन के मालिक पर पेनल्टी या फिर सजा मिल सकती है।

आईफोन की खामियों पर 1 करोड़ का ईनाम

हैकिंग में रुचि रखने वालों के लिए दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी एपल पैसे कमाने का सुनहरा मौका लाई है। कंपनी ने उन हैकरों को लाखों–करोड़ों रुपये देने की घोषणा की है, जो उनके उत्पाद में खामियां ढूंढे और कंपनी को बताए। जो हैकर खामियां ढूंढ़ने में कामयाब हो जाएंगे, उनको एपल

तकरीबन 16 लाख रुपये से लेकर एक करोड़, 33 लाख रुपये तक इनाम के तौर पर देगी।

प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों के नाम ट्रेन

इंडियन रेलवे किराये से इतर आमदनी बढ़ाने का हर संभव तरीका आजमा रहा है। दरअसल, रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे की आय बढ़ाने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा रहे हैं। लक्ष्य इस वित्त वर्ष के आखिर (31 मार्च 2017) तक नॉन–फेयर रेवेन्यू (एनएफआर) को मौजूदा 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का है। एनएफआर के अनुसार आधे डिस्प्ले यूनिट्स में रेलवे संबंधी सूचनाएं दी जाएंगी और आधे में ऐडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। मकसद खास सूचना की तलाश कर रहे या इंतजार कर रहे यात्रियों का ध्यान आकर्षित करना है। समय पर सूचना देकर ना केवल यात्रियों को ज्यादा संतुष्ट कर पाएगा बल्कि यह रेलवे के लिए राजस्व उगाही का महत्वपूर्ण साधन भी साबित होगा। यह आउट ऑफ होम (OOH) ऐड को नए स्तर पर लाएगा।

हर्बल टूथपेस्ट ने उड़ाई विदेशी कंपनियों की नींद

भारतीयों में हर्बल प्रॉडक्ट इस्तेमाल करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका असर टूथपेस्ट कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। भारतीय कंपनियों, मसलन डाबर और पतंजलि ने टॉप मल्टिनैशनल कंपनियों जैसे

कोलगेट और हिंदुस्तान युनिलीवर को पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह से मल्टिनैशनल कंपनियों को भी 'नैचरल' प्रॉडक्ट लांच करना पड़ रहा है। कॉम्पिटिशन के लिहाज से उन्हें इनके दाम भी कम रखना पड़ा है। बाबा रामदेव की हरिद्वार स्थित कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कई देश के एफएमसीजी मार्केट को लुभाने के लिए कम दाम वाले 'हर्बल' प्रॉडक्ट लांच किए हैं।

भारत में हर्बल और आर्युवेदिक टूथपेस्ट का मार्केट तकरीबन 800 करोड़ रुपये का है जबकि टूथपेस्ट का कुल मार्केट 7,500 करोड़ रुपये का है। यानी हर्बल टूथपेस्ट का मार्केट पूरे मार्केट का 10 प्रतिशत है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि हर्बल टूथपेस्ट का मार्केट बाकी टूथपेस्ट मार्केट के मुकाबले 20 प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है।

ब्रिटेन–अमेरिका में भारतीय छात्रों की बढ़ेगी संख्या

स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या अगले पांच साल में 50 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि उनके परिवारों की आय कई गुना बढ़ेगी। भारतीय छात्र अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अनुभव प्राप्त करने और भारत तथा वैश्विक

स्तर पर शीर्ष स्तर पर पेशेवरों में अपने आपको स्थापित करने के इच्छुक हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी के दौरान चीन के छात्रों की अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने की गतिविधियों में 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। अब भारतीय छात्रों के लिए वही स्थिति है।

ट्रेन में सबसे बड़ी डकैती

रिजर्व बैंक इंडिया का 342 करोड़ रुपया लेकर जा रही ट्रेन को लूट लिया गया। चलती ट्रेन में अपनी तरह की पहली डकैती की यह घटना है तमिलनाडु के सलेम की। जहां से आरबीआई के द्वारा बुक कराया गया कोच गुजर रहा था, तभी डकैतों ने कोच की छत काटकर लूटपाट को अंजाम दिया। शातिर अपराधी कितनी रकम ले गए हैं, इसका पता नहीं चल सका है। ट्रेन में 228 ट्रंक में 342 करोड़ रुपए के नोट थे। कुल रकम का वजन करीब 23 टन बताया जाता है। डकैतों ने दो ट्रंक खोले थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरबीआई ने यह रकम चेन्नई से 350 किलोमीटर दक्षिण–पर्वू में स्थित सलेम के पांच बैंकों से इकट्ठा की थी।

कॉल ड्रॉप पर 10 मिनट का टॉकटाइम

कॉल ड्रॉप की समस्या से हर कोई परेशान है। मगर इस परेशानी से अब आप फायदा भी उठा सकते हैं। इसके लिए कॉल ड्राप होने पर बस आपको एक एसएमएस करना होगा और 10 मिनट का फ्री टॉकटाइम आपका हो जाएगा। हालांकि यह ऑफर सिर्फ

वोडाफोन ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। दरअसल दिग्गज टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत अगर किसी भी ग्राहक की कॉल अचानक कट जाती है तो उसे 10 मिनट का फ्री टॉकटाइम दिया जाएगा। वोडाफोन इंडिया ने एक बयान में कहा, "कंपनी की वोडाफोन डिलाइट बोनांजा स्कीम के तहत किसी भी ग्राहक की फोन कॉल में रुकावट आने के बाद उसे 10 मिनट का टॉकटाइम दिया जाएगा।" इस तरह मिलेगा फ्री टॉकटाइम– अगर किसी वोडाफोन कस्टमर की कॉल ड्रॉप होती है, तो फ्री टॉकटाइम के लिए ग्राहकों को एक एसएमएस करना होगा। इसके लिए ग्राहक को 199 पर 'BETTER' लिखकर भेजना होगा और टॉकटाइम मिल जाएगा। आपको बता दें कि देशभर में विभिन्न ऑपरेटरों के नेटवर्क पर उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप की दिक्कत झेलनी पड़ रही है। सरकार ने ऑपरेटरों के साथ बैठक कर उन्हें इस स्थिति में सुधार करने को कहा है।

दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर हटा बैन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली–एनसीआर में 2000 सीसी तक की डीजल गाड़ियों

पर लगा बैन हटा दिया। हालांकि, कस्टमर्स के लिए डीजल कार खरीदना महंगा हो जाएगा क्योंकि कोर्ट ने 1 प्रतिशत ग्रीन सेस लगाने को कहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियां ये सेस कस्टमर्स से ही वसूलेंगी।

कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी एक सरकारी बैंक में अलग से अकाउंट खोलेगा। इसमें ये ग्रीन सेस डिपॉजिट किया जाएगा। जैसे–दिल्ली–एनसीआर से महिंद्रा स्कॉर्पियो (2180 सीसी) का एक्स शोरूम प्राइस 12.70 लाख रुपए है। अब इसे खरीदने पर 1 फीसदी का ग्रीन सेस देना होगा। यानी इसका एक्स शोरूम प्राइस करीब 12 हजार रुपए बढ़ जाएगा।

सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी

स्पेक्ट्रम नीलामी का अब तक का सबसे बड़ा दौर 29 सितंबर 2016 से प्रारंभ होगा। इसमें बेस प्राइस पर 5.63 लाख करोड़ रुपये मूल्य की मोबाइल एयरवेव के लिए बोली लगेगी। नीलामी के लिए आवेदन की सूचना (एनआइए) जारी करते हुए दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने कहा कि मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। कंपनियों की सुविधा के लिए इस बार नियमों को काफी आसान बनाया गया है। कुल मिलाकर 2,354.55 मेगा हर्ट्ज बैंड की मोबाइल एयरवेव फ्रीक्वेंसियों की नीलामी होगी। इनमें 700, 800, 900, 1800, 2100 तथा 2300 मेगा हर्ट्ज के वे बैंड शामिल हैं जिनका उपयोग 4जी सेवाओं में किया जा सकता है। इनमें 1800 मेगा हर्ट्ज बैंड के तहत कुल 197 मेगा हर्ट्ज, तथा 800 मेगा हर्ट्ज बैंड (सीडीएमए बैंड) के तहत कुल 37.5 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसियां शामिल हैं।

चालू वर्ष के दौरान सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से कम से कम 64,000 करोड़ रुपये तथा विभिन्न शुल्कों से लगभग 98,995 करोड़ रुपये की रकम हासिल होने की उम्मीद है।

कैंसर एवं एड्स की दवाईयां हुई सस्ती

कैंसर और एचआईवी समेत कई बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 24 दवाएं औसतन 25 फीसदी सस्ती हो गई हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने शेड्यूल–1 की दवाओं के दामों को रिवाइज्ड कर 35 फीसदी तक की कमी की है। एनपीपीए ने ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर 2013 के तहत 31 दवाओं के रिटेल प्राइस पर कैप लगाया है। अथॉरिटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 24 में से कुछ दवाओं के दाम 10 से 15 फीसदी, वहीं कुछ के दाम 30 से 35 फीसदी तक घटाए हैं। कुल मिलाकर औसत कटौती 25 फीसदी हुई है। सरकार ने ऐसे चिकित्सकीय खंडों में प्राइस फिक्स किए हैं जहां इन आवश्यक दवाओं की बिक्री 1 फीसदी से अधिक होती है। इसके अलावा अथॉरिटी लगातार सभी दवाओं की रिटेल पर भी नजर बनाए हुए है। ❑❑

हमारा अधिकांश व्यापार घाटा चीन से वस्तुओं के आयात के कारणः

श्री कश्मीरी लाल

जोधपुर 28 जुलाई 2016ः स्वदेशी आंदोलन भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही जुड़ा हुआ है। भारत को पुनः सोने की चिड़िया का गौरव प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारियों ने स्वदेशी अपनाओं का नारा दिया था। 12 दिसंबर 1930 को बाबू गेनू स्वदेशी के लिए शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात को समझा कि विदेशी वस्तुओं का भारत में व्यापार हमारे लिए आर्थिक नुकसान एवं राष्ट्रीय दासता के लिए जिम्मेदार तत्व है। उपरोक्त कथन स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक श्री कश्मीरी लाल ने शहीद बाबू गेनू स्मृति स्वदेशी विचार व्याख्यान माला में ''वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में स्वदेशी ही एक मात्र विकल्प'' विषय पर बोलते हुए मोटर मर्चेंट एसोसिएशन सभागार में कहें।

उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी जागरण मंच चीन द्वारा भारत की एन.एस.जी. में सदस्यता के विरोध को लेकर क्षोभ प्रकट करता है क्योंकि हमारा अधिकाशं व्यापार घाटा चीन से वस्तुओं आयात के कारण ही हैं। अजहर मसूद हो या महमूद लखवी जैसे आतंकवादी, चीन उनके समर्थन में खड़ा होकर भारत के प्रति अपनी शत्रुता हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रकट करता है। ऐसे में चीनी वस्तुओं का आयात करना व इनका उपयोग करना शत्रु राष्ट्र का आर्थिक पोषण करना है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रव्यापी अभियान चला कर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने का सरकार व जनता से आहवान करता है। मंच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सदा से विरोध कर रहा है। एफ.डी.आई. से रोजगार बढने कि जो बात की जा रही है, आकंड़े बताते है कि इससे रोजगार बढ़ने की जगह घटा है और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्वचालित प्रणाली द्वारा निर्माण व उत्पादन करती है जिससे केवल कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त होता है। मंच का मानना है कि एफ.डी.आई. नीति से भारत को लाभ कि जगह नुकसान ही हो रहा है। 9 अगस्त से ''एफ.डी.आई. वापस जाओं'' उद्घोष के साथ पूरे देश में प्रत्येक जिला स्तर पर मंच द्वारा इसका विरोध शुरू होगा। आगामी 3 व 4 सितंबर 2016 को दिल्ली में मंच के सभी पदाधिकारी एकत्र होकर आगे की रणनिति तय करेंगें।

व्याख्यान माला कि अध्यक्षता करते हुए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राधेश्याम शर्मा ने कहा कि आज हमें पुनः एक नये स्वतंत्रता आंदोलन की जरूरत है जिसमें हम विदेशी कंपनियों के सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करे तभी हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र होंगे। मैं मंच के कार्यकर्ताओं का साधुवाद देता है कि वे संपूर्ण भारत में इस पुनित कार्य को निस्वार्थ भाव से पूर्ण कर रहे है। उन्होनें आगे कहा कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एक बार पुनः पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो रही है। सभी जगह योग का डंका बज रहा है। भारतीय संस्कृति व पारिवारिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा बढ़ रही है।

व्याख्यानमाला के मुख्य अतिथि उत्कर्ष संस्थान के निदेशक निर्मलजी गहलोत ने कहा कि वर्तमान समय भौतिकवाद का है। हमारी युवा पीढ़ी तेजी से विदेशी संस्कृति, विदेशीब्रांड, विदेशी खान–पान की ओर आकर्षित हो रही है। जिससे देश की प्रतिभा व धन का पलायन हो रहा है और देश को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा हैं। मैं मुक्त कंठ से मंच को धन्यवाद देता है कि मंच इस नुकसान को निस्वार्थ भाव से रोकने में लगा हुआ है। हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सम्मिलित रूप से मंच के साथ कंधा से कंधा से मिलाकर इस परोपकारी कार्यों को गति प्रदान करें।

व्याख्यानमाला के विशिष्ट अतिथि मोटर मर्चेंट एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष श्री सोहनलाल मंत्री ने कहा कि आज देश की आर्थिक नीतियां विदेशी ताकतों से प्रभावित हो रही हैं। इसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम देश की आर्थिक हितों को देखते हुए नीतियों का चयन करे और आर्थिक विषमनता को दूर करें।

मंच के प्रांत संयोजक धर्मेन्द्र दूबे ने कहा कि वर्तमान समय में देश के 388 जिलों में स्वदेशी जागरण मंत्र की ईकाईयां सक्रिय है। दुनिया के 124 देशों के 1112 शहरों में मंच की वेबसाइट नियमित रूप से देखी जाती है। इस अवसर पर मंच के मीडिया प्रमुख मिथिलेश झा सहित शहर के गणमान्य लोग व मंच के दायित्वान कार्यकर्ता उपस्थित थे। ❑❑